संपूर्ण समाधान प्रश्नावली

पहला संस्करण - ८ अगस्त २०२०

साक्षात्कार – प्रेमजीत सिरोही

(दार्शनिक, वक्ता, लेखक एवं संस्थापक ULM)

प्रश्नकर्ता -अम्बरीष मिश्रा
१४ जुलाई २०२०

साक्षात्कार- प्रेमजीत सिरोही

Overview

1) **संक्षेप में, संपूर्ण समाधान क्या है?**

संपूर्ण समाधान सभी के सुनहरे जीवन के लिए एक व्यवस्था है। विश्व वसुधैव कुटुम्बकम वास्तव में हो इसके लिए यह एक विश्व स्तर का कांसेप्ट है। संपूर्ण समाधान का यहाँ मतलब है सभी अपना इच्छा का जीवन जी सकें, पूरे मज़े में जी सकें। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद की शिक्षा ले सके, पसंद का रोज़गार कर सके, पसंद के उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सके। यानी अपनी इच्छा के सभी सुख सुविधाएं हासिल कर सके। इसमें सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। वास्तविक लोकतंत्र और समानता का अनुभव करेंगे। जीवन में सभी प्रकार की सुरक्षा, स्वतंत्रता और शांति मौजूद होगी।कोई हिंसा, कोई प्रदुषण, कोई तनाव जीवन में नहीं होगा और विभिन्न तरह के सुख निरंतर उपलब्ध होंगे सभी को।

अब यह कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के, समाज जनित संपत्ति के निर्माण के लिए एक विकेंद्रीकृत – केंद्रीकृत दृष्टिकोण लिया गया है। यह अगली प्रणाली लोकतांत्रिक है, इसमें विविधता और एकरूपता दोनों है और शासन एक विकेन्द्रीगत-केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा प्रबंधित है। एक प्रणाली जिसमें सत्ता हर समय नागरिकों के पास रहती है और फिर भी प्रबंधन / प्रशासन का एक केंद्रीकरण है। यदि यह मॉडल अस्तित्व में आता है, तो अभी होने वाली समस्याएं जन्म लेने से दूर हो जाएंगी। नयी व्यवस्था से यहां मतलब है एक नया अर्थशास्त्र, नया राजनैतिक मॉडल, नया सामाजिक मॉडल, नया शैक्षिक मॉडल, नया पारिवारिक मॉडल और मूल में एक नया दर्शन। यह संयुक्त रूप से संपूर्ण समाधान व्यवस्था है।

2) **ULM (Universal Life Management) संस्था का कार्य और लक्ष्य क्या है?**

ULM संस्था का कार्य है, इस संपूर्ण समाधान को, इस पूरी व्यवस्था को सभी लोगो तक पहुँचाना और यदि सब लोग चाहें की यह व्यवस्था आ जाये तो उसको लाने का काम करना। इसके साथ ULM एक ऐसे अनोखे संवाद मंच को विकसित कर रहा है जिसमे विश्व के जितने भी मनीषी हैं आ सकें और मानव कल्याण हेतु अपने समाधान व शोध रख सकें, ताकि इन चर्चाओं से जनता बौद्धिक लाभ उठाये। चर्चाएं इस तरह से करवाई जाएँगी कि लोगों के लिए स्पष्टता उभर के आए और अंततः एक सही व्यवस्था के लिए वे अपना शिक्षित मत दे पाएं।

इसके अतिरिक्त यह संस्था, व्यवस्था एवं जीवन दर्शन से सम्बंधित अपने शोध समाज में रख रहा है ताकि मानव समाज को सुखी करने हेतु एक वैचारिक पुनर्जागरण हो। इन सब खोजों को विभिन्न फॉर्मेट में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जैसे किताबें, शोध पत्र, इंटरव्यू, online course, workshops ,फिल्म, कहानियां, इत्यादि। इस तरह ULM के अनेक कार्यक्रम, वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यवस्थागत समाधान की परंपरा को विकसित कर रहे हैं एवं आम जनता में से योग्य नेतृत्व को उभारने का काम कर रहे हैं ताकि समाज एक सोची समझी दिशा में गति करे।

3) **आपको क्यों लगता है कि हमें पूरे सिस्टम को बदलने जैसे एक बड़े कदम की आवश्यकता है?**
मुझे इसलिए लगता है की पूरे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है क्यूंकि जब में समस्या की खोज में गया तो मैंने पाया की यहां सभी चीज़ें एक दुसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी जो व्यवस्था होती है, कोई भी जो कांसेप्ट होता है उसकी एक थीम होती है। मौजूदा व्यवस्था की भी एक थीम है। अगर हम उसमें कोई भी एक चीज़ बदलते हैं तो वह दुसरे जगह पे कोई ख़राब नतीजे देती है, माने साइड इफेक्ट्स देती है, चूँकि वह बदलाव उस थीम के अनुरूप नहीं होगा।

अगर मूल में हम कोई बदलाव करेंगे तो सारा थीम ही बदल जाता है। **अभी जो कांसेप्ट है वह मूल में ही सही नहीं है**। जब आप मूल को सही करने जायेंगे तो एक तरह से पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, अगर मूल ठीक होता है और ऊपर कहीं कोई एक आद जगह गड़बड़ी रहती है तो वह एक आद जगह ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर मूल में समस्या है तो पूरा ही बदलना पड़ेगा।

4) **क्या हमें इस देश का नेतृत्व करने के लिए ईमानदार लोगों की आवश्यकता नहीं है? आखिर कुछ लोग नई व्यवस्था चला रहे होंगे और अगर वे ईमानदार और सही नहीं होंगे तो नई व्यवस्था भी तो सही से नहीं चल पायेगी?**
नहीं, हमें नयी व्यवस्था में ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है बल्कि सक्षम लोगों की ज़रूरत है। जिनमें उस पद पर कार्य करने की क्षमता हो, केवल उसकी ज़रूरत है। ईमानदार बेईमान जैसा आदमी होता नहीं। ख़राब परिस्थिति में ईमानदारी और बेईमानी जैसी बात उठती है । ख़राब व्यवस्था में अधिकतम ख़राब परिस्थितियां बनी रहती हैं और 99% लोग बेईमान हो जाते हैं और 1% कोई है जो उस अवस्था में भी ईमानदार बने रहते हैं। लेकिन वो 1% लोग कभी नेतृत्व में पहुँच नहीं पाते। एक तो ईमानदार चुनाव मैदान में पहुँच नहीं पाते और दूसरा किसी तरह पहुँच भी गए तो 99% लोग अपने लाभ के लिए बेईमान के झांसे में आकर बेईमान को ही चुनते है। यानी बेईमान लोग बेईमान को चुनते है क्यूंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है की उन्हीं से उनको लाभ मिलेगा। ख़राब व्यवस्था में बेईमान और ईमानदार का कांसेप्ट होता है,अच्छी व्यवस्था में यह अप्रासंगिक हो जाता है। सही व्यवस्था में सक्षम का कांसेप्ट होता है।

5) **संपूर्ण समाधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?**
संपूर्ण समाधान व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है की यह व्यक्ति को पूरी एवं परम आज़ादी देती है। यहां परम स्वतंत्रता का मतलब है की वो जैसा जीवन जीना चाहे, जिस प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहे, उसको वो सारी चीज़ें इस व्यवस्था में सदैव ही उपलब्ध रहेंगी। और इससे व्यवस्था की सारी पावर जनता में ही निहित रहने वाली है, यह इसकी ख़ूबसूरती है। इंसान जैसा मूल में है उस हिसाब से यह व्यवस्था बनी है, नाकि इंसान को व्यवस्था के हिसाब से ढालने की कोई जद्दोजहत है।

6) **क्या अमीर और शक्तिशाली द्वारा प्रतिरोध नहीं होगा?**
जी उनके द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं होगा, क्यूंकि उनका जीवन आज से भी बेहतर हो जायेगा इस व्यवस्था में, इसलिए नहीं होगा। व्यवस्था को जानकार उनको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। आज की

व्यवस्था में कुछ फायदों के लिए कई परेशानियां पालनी पड़ती हैं। प्रस्तावित व्यवस्था को समझने पर आप पाएंगे की यह हर इंसान के लिए फायदेमंद है और नुकसान कोई नहीं।

Economic model

7) मौजूदा अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या आप देखते हैं, वह क्या है?

मौजूदा अर्थशास्त्र केवल 10% लोगों को entertain करता है। 90% लोगों को वह अपने से बाहर कर देता है, या उनको दास, मजदूर, ग़रीब आदि बना कर रखता है। यह आज के अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी दिक्कत है। आज का जो अर्थशास्त्र है वह केवल 10% लोगों के लिए है। 90% लोगों को वह 10% का साधन बना के रख देता है। यह इस अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी ग़लती, दुविधा या ख़राबी बोलो, जो भी आप बोलो।

8) क्या आर्थिक असमानता को कम करने के लिए अमीरों पर भारी कर लगाना ज़्यादा सरल उपाय नहीं है, जिससे सरकार विभिन्न गरीबी कम करने के कार्यक्रम चला सके, और सोशल सिक्योरिटी आदि प्रदान कर सके?

नहीं,यह तो सरकार कुछ हद तक कर भी रही है और यह कोई बहुत सटीक उपाय नहीं है। इससे एक वर्ग पर अलग तरह का जोर पड़ता है क्योंकि आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। पहले आप कुछ ही लोगों को अमीर बनने की जगह दे रहे हो, फिर उनसे धन खींचने का प्रयास कर रहे हो तो उन पर यह मानसिक असर पड़ता है। उनको लगता है कि उनके हिस्से से खींचा जा रहा है फिर वह उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहां से दुविधा शुरू होती है, विरोधाभास शुरू होता है। काला बाजार, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और दुसरे क्राइम शुरू हो जाते हैं। सरकार नियमों के द्वारा जितना धन कुबेरों से धन खींचना चाहेगी उतना सरकार और उद्योगपतियों के बीच में द्वंद पैदा हो जायेगा, जोकि वह पैदा करेंगे नहीं क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ सरकारें चला रही होती हैं उन्हें भी पार्टी के लिए फण्ड चाहिए होता है जो उद्योगपतियों से मिलता है। तो कुल मिलाकर वे नेक्सस बना लेते हैं और वह हो नहीं पाता जो आप कह रहे हैं कि वह अमीरों का पैसा उठाकर गरीबों को दे दे। .

और दूसरी बात यह है की जो विधि है अर्थशास्त्र की उसमें उतना पैदा नहीं होता है की अगर वो उन 10% अमीरों का उठा के गरीबो को दे देंगे तो भी वह ऊंट के मुँह में जीरा जैसा ही होगा। कुछ ख़ास नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है की व्यवस्था ऐसी बना ली जाये की जिसमें पैदा ही इतना हो जितनी की वास्तविक मांग है। अगर अर्थशास्त्र में बदलाव नहीं किये गए तो घूम-फिर के पैसा वहीँ 10 % के पास केंद्रित हो जायेगा। यह इस अर्थशास्त्र का स्वभाव है।

9) यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर आपके क्या विचार हैं?

यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक अच्छी योजना है मौजूदा व्यवस्था को रखते हुए, अगर ठीक से उसकी economic planning की जाए तो। अगर आप मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखते हैं, मौजूदा अर्थशास्त्र को बनाए हुए रखते हैं, तो यूबीआई से धीरे-धीरे एक जो जीवन स्तर है लोगों का वह अच्छा हो जाएगा। हालांकि वहां असमानता रहेगी, विषमता रहेगी, उंच नीच का भाव रहेगा, यह सब दिक्कतें

रहेंगी मगर फिर भी जो क्राइम है वह कम हो जाएगा, लोग बीमार कम होंगे और जीवन आज से काफी बेहतर हो जाएगा, इस तरह से बढ़िया है।

10) संक्षेप में बताइये, आपका नया अर्थशास्त्र क्या है?

नया अर्थशास्त्र, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें मैंने वह सारे कारण हटा दिए हैं जो किसी भी नकारात्मकता को पैदा करते हैं और वह सारे कारण इसमें मैंने डाल दिए हैं जो की सारी सकारात्मकता को पैदा करते हैं। इसमें निवेश नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, परस्पर विनिमय नहीं है, इसमें वस्तु एवं श्रम का मूल्यांकन नहीं है, यह सारी चीजें इसमें नहीं है। इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं है, इसमें सहयोगिता है, सहभागिता है, तो संक्षेप में बोले तो यह इसके गुण धर्म हैं। ऐसा अर्थशास्त्र जो कि सबको परम स्वतंत्रता देता है सब चीज़ में। चाहे वो पसंद की शिक्षा लेने में, पसंद का काम करने में और चाहे सारी सुख सुविधाओं को भोगने में हो। यह व्यवस्था लोगों को असीमित स्वतंत्रता या जगह देती है और यहां असीमित से मतलब है आप जितना चाहते हैं उतना। इसको आप बोल सकते हैं “sky is the limit”- कांसेप्ट पर यह आधारित है। नए अर्थशास्त्र को समझने से पहले हमें मौजूदा अर्थशास्त्र को समझना होगा। हमें अर्थशास्त्र के मौजूदा मॉडल की सीमाओं को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि विश्वशांति, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव कल्याण के वांछित परिणाम हमारे अर्थशास्त्र के मौजूदा मॉडल द्वारा क्यों संभव नहीं है।

आज तक के अर्थशास्त्र की मुख्य नीति

आजतक ये नीति ऐसी हैं कि जितनी मुद्रा या धन आपके पास है, आप उतनी ही मांग बाजार में कर सकते हैं। यानिकि हमारी मांग हमारे पास जो धन है, उस पर निर्भर करती है। इससे होता ये है कि बाजार में हम अपनी जरूरतों के आधार से पूरी मांग नहीं कर पाते। इससे होता ये है कि बाजार में मांग बहुत कम रहती है। अब जब मांग कम रहती है तो बाजार मांग के आधार से ही निर्माण करता है। यानिकि निर्माण भी कम ही होता है। अब जब बाजार में निर्माण कम होता है तो इसका अर्थ है रोजगार कम पैदा होता है। अब जब रोजगार कम पैदा होता है तो समाज में बेरोजगारी पैदा हो जाती है। क्योंकि आय तो रोजगार से ही होती है आज के समाज में। जिनके पास रोजगार नहीं होता तो उनकी आय भी नहीं होगी। अर्थात बिना आय वाले लोग तो समाज की भीख पर ही जिंदा रहते हैं क्योंकि वो तो बाजार में मांग भी कर नहीं सकते। और जिनकी आय कम है वो भी पर्याप्त मात्रा में मांग नहीं कर सकते। केवल जिन थोड़े से लोगों के पास पर्याप्त धन होता है वो ही केवल अपनी सम्पूर्ण मांग कर पाते हैं। इस आर्थिक नीति के कारण सदैव ही मांग की कमी बनी रहती है बाजार में क्योंकि आय कम रहती है क्योंकि रोजगार कम रहता है। अर्थात देश और दुनिया में एक बड़ा वर्ग सदैव ही गरीब रहता है। ये कहानी है आज के अर्थशास्त्र की नीतियों की। इसके कारण अधिकतर मनुष्य गरीबी का जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। और जबतक ये आर्थिक नीति नहीं बदलती तबतक सबके सुखी होने की कोई संभावना नहीं है।

ये तो आप भी जानते हैं कि आदमी के पास जितना धन होता है वो सारे धन का प्रयोग तो आज की खरीदारी में करता भी नहीं है, कुछ तो भविष्य के लिए बचाकर भी रखता है क्योंकि अभी के सिस्टम में उसे अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। अभी सरकारों ने इस दिशा में बहुत ही कम कार्य किया है, जिस कारण लोग अपने भविष्य को सुरक्षित अनुभव नहीं कर पा रहे हैं पर चलो यदि वो धन को ना भी बचाये भविष्य के लिए तो भी अब लोगों के पास जितना धन होगा, वो केवल उतनी ही मांग कर सकते हैं बाजार में। वो कभी भी जीवन में अधिकतम मांग कर ही नहीं सकते जबतक कि उनके पास पर्याप्त धन ना आ जाय। और पीछे इतिहास को देखते हुए कह सकते हैं कि आजतक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी नागरिकों की खरीदने की शक्ति पर्याप्त रही हो। हम इस चित्र से ये बात आसानी से समझ भी सकते हैं।

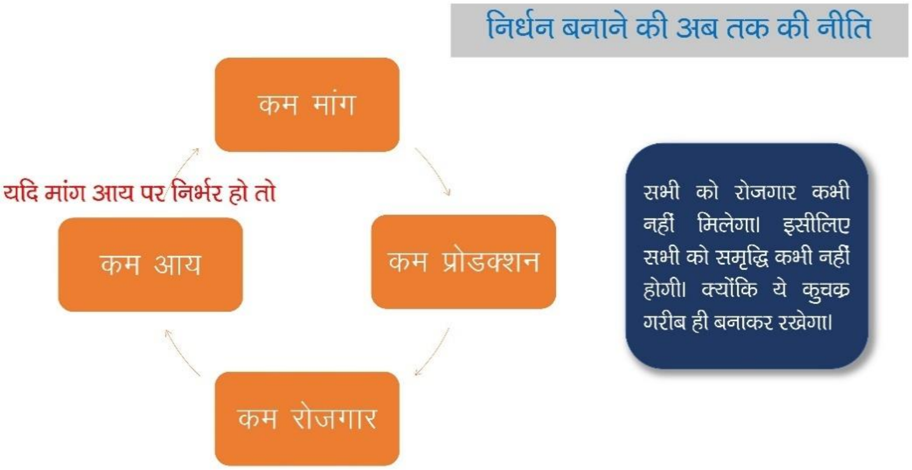
निर्धन बनाने की अब तक की नीति

सभी को रोजगार कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी को समृद्धि कभी नहीं होगी। क्योंकि ये कुचक्र गरीब ही बनाकर रखेगा।

इस नीति को यदि आप ध्यान से देखें तो पायेंगे कि जबतक हमारी मांगे धन पर निर्भर रहेंगी तबतक हम पर्याप्त मांग नहीं कर सकेंगे। पर्याप्त निर्माण भी नहीं हो सकेगा वस्तु और सेवाओं का। पर्याप्त रोजगार भी नहीं पैदा हो सकेगा। पर्याप्त आय भी नहीं हो सकेगी। जब पर्याप्त आय नहीं होगी तो फिर से पर्याप्त मांग नहीं हो सकेगी। और ये कुचक्र ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा सदैव। ये चक्र अधिकतर मनुष्यों को गरीब ही रखेगा। और रख रहा है। फिर से समझें, क्योंकि धन आता है रोजगार से, रोजगार आता है निर्माण से, निर्माण होता है वस्तु और सेवाओं की पर्याप्त मांग से, मांग आती है पर्याप्त धन से। अब आप समझ गये होंगे कि सबके पास पर्याप्त धन होगा ही नहीं क्योंकि सबके पास तो रोजगार है नहीं। और सबके पास राजगार इसलिए नहीं है क्योंकि बाजार में पर्याप्त मांग ही नहीं है। भाई यदि बाजार में मांग ही न्यूनतम होगी तो बाजार न्यूनतम प्रोडक्शन ही करेगा और उससे न्यूनतम रोजगार ही पैदा होगा और फिर उससे न्यूनतम आय ही उत्पन्न होगी। और ये कुचक्र ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये नीति रहेगी, ये कुचक्र ऐसे ही अधिकतर लोगों को गरीब बनाकर रखेगा। इस नीति के कारण सभी लोग कभी भी समृद्ध नहीं हो पायेंगे।

आप समझ गये होंगे कि जबतक ये नीति रहेगी हम सबकी गरीबी बनी ही रहेगी। कुछ लोग जोकि इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं का निर्माण करते हैं केवल वो ही बहुत अधिक अमीर होते हैं। और ये लोग कुल जनसंख्या का केवल 1-10 प्रतिशत होते हैं। इस नीति के रहते अधिकतम लोगों की गरीबी

कोई दूर नहीं कर सकेगा। इस नयी नीति को देखें जो कि मैंने इस उपर वाली नीति में छोटा सा परिवर्तन करके बनाई है।

अर्थशास्त्र की मुख्य नीति में परिवर्तन

मैंने इस नीति में एक परिवर्तन किया है। मांग करने के लिए जो धन की अनिवार्यता है उसको मैंने हटा दिया। अर्थात अब इस नीति के अनुसार सब अपनी अपनी मांगे पर्याप्त रूप से करते रह सकेंगे। मांग करने के लिए अब धन की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखें इससे क्या होगा, हमारे समाज मं सभी वस्तुओं की मांग 100 प्रतिशत हो जायेगी। अब इस 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 100 प्रतिशत निर्माण करना होगा। 100 प्रतिशत निर्माण के कारण 100 प्रतिशत रोजगार उत्पन्न हो जायेगा। जिसके कारण 100 प्रतिशत रोजगार भी देना होगा। क्योंकि 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने के लिए 100 प्रतिशत मिलों, मशीनों, बिजली, सड़क, पानी, मालवाहक वाहन और बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होगी और इन सब आवश्यकताओं के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी यानिकि सीधे तौर पर कहूं तो 100 प्रतिशत रोजगार होंगे सरकार के पास सदैव ही। तो इसका अर्थ सभी लोगों के पास रोजगार होगा। दूसरे शब्दों में सभी समृद्ध हो जायेंगे। आगे चित्र से भी समझ सकते हैं।

नये अर्थशास्त्र में समृद्ध बनाने की नीति

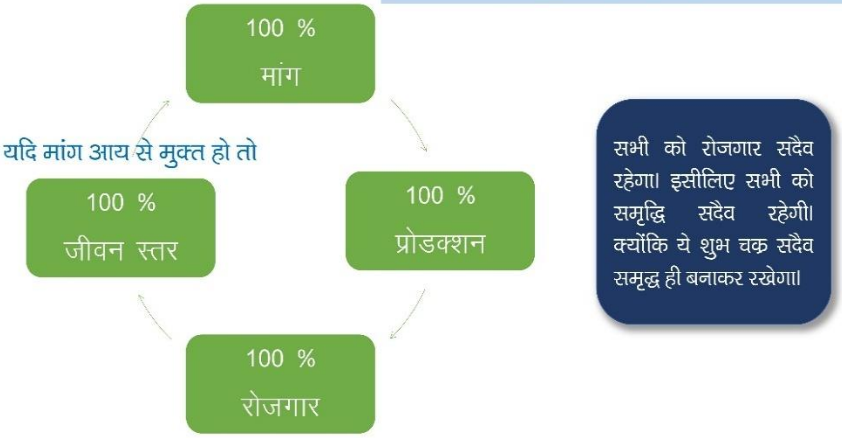

सभी को रोजगार सदैव रहेगा। इसीलिए सभी को समृद्धि सदैव रहेगी। क्योंकि ये शुभ चक्र सदैव समृद्ध ही बनाकर रखेगा।

देख रहे हैं ना कि अब इस नीति से क्या हो सकता है। बस मैंने आपके खरीदने की शक्ति को धन की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। नीति में एक छोटा सा परिवर्तन कितना आश्चर्यजनक परिणाम ला सकता है ये हम उपर दिये हुए चित्र से भली भांति समझ सकते हैं। लोगों को सच्ची स्वतंत्रता तभी अनुभव होगी जबकि वो समानता से सारी समृद्धि को भोगने के लिए स्वतंत्र होंगे। लोग जो सीखना चाहें वो सीख सकें, जो करना चाहे वो कर सकें और जो भोगना चाहें वो भोग सकें तभी सही मायने में कहा जायेगा कि अब हम स्वतंत्र हैं। जो भी चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने को मिल रहा है। आगे मैंने मुद्रा की परिभाषा भी बदली है। मुद्रा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आपका बैंकअकाउंट सरकार के पास होगा। सरकार आवश्यकता के अनुसार सबकी मांग करने की सीमा तय करती रहेगी। जिसके आधार से सभी अपनी ईच्छानुसार जो भोगना चाहते

हैं वो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करते रह सकंगे। हां बस इसके लिए एक शर्त होगी। और शर्त ये होगी कि आपकी ईच्छानुसार सरकार आपको जो रोजगार दे रही होगी उसको आपको करना होगा, यदि आप 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के हैं तो। यदि आप ये सहयोग नहीं कर रहे होंगे तो आपको इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो बस फिर कभी भी कुछ भी आप सरकार से ले सकते हैं और उसका उपभोग करते रह सकते हैं। एक बार संतुलन की अवस्था आ जाएगी तो सम्भवतः ये सीमा रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। रोजगार की गारंटी सरकार की तरफ से होगी ही। यदि सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है तो इस अवस्था में आपको इस नीति का लाभ मिलता रहेगा। कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार आपको होगा। रोजगार गारंटी के कारण यदि सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पाती है तो भी सरकार उसको पूरा अधिकार देगी सभी कुछ प्राप्त करने का। इस नीति के द्वारा सभी की मांगे एवं सभी को रोजगार एक साथ हो जायेगा। जो ऐसी वस्तुएं होंगी जिनकी कि संसार में कमी होगी तो सरकार उन वस्तुओं को व्यक्तिगत स्तर से नहीं देगी परंतु सामाजिक स्तर से आपको प्राप्त करायेगी। तो इससे क्या होगा कि जो संसाधन इस संसार में कम पाये जाते हैं वो भी सभी को पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सकेंगे। और प्राकृतिक ससाधनों का दुरपयोग भी रूकेगा इस नीति से। आओ देखें कि ये कैसे हो सकता है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले सरकार सारी आवश्यक सरकारी नियुक्यिां करेगी और साथ ही सॉफ्टवेयर इंजिनियर्स का एक बड़ा पेनल नियुक्त करेगी जोकि जल्दी से इंटर्नेट पर वेबसाइट के रूप में एक ऐसे आनलाइन सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगा जिसमें पूरे देश के सभी नागरिक अपना अकाउंट बना सकेंगे और जिसके अन्दर अपनी सभी मांगो को भर सकेंगे। और अपने बारे में सारी जानकारी भर सकेंगे कि वे क्या योग्यता रखते हैं, क्या क्या कार्य करना उन्हें आता है, इसके अलावा वे क्या करना चाहते हैं, यदि उनकी योग्यता है परंतु वे सीख नहीं पाये तो क्या वे सीखना चाहते हैं आदि आदि। लोग सबकुछ सीख सकेंगे। सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। जिन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता है उनके लिए उनके आस पास कम्पयूटर आपरेटर्स को नियुक्त करेगी जिनके माध्यम से लोग अपनी मांगे और अपना प्रोफाईल बना सकेंगे। जैसेकि उन्हें एक माह में कितना गेंहू, मक्का, चीनी, दूध, घी, कपड़ा, तेल, मसाले, सब्जियां, सभी प्रकार के फल, तिल, सेंट्स, मिठाइयां आदि ऐसी मांगे जोकि दिन, सप्ताह या माह के आधार से होती हैं। इसके अलावा मोटर साइकिल, मोटरकार, मोबाइल, टी. वी., वाशिंग मशीन, सभी प्रकार के फर्नीचर, रहने के लिए एक घर आदि अपनी अपनी इच्छानुसार इन सभी मांगों को आनलाइन भर सकेंगे। अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, और भविष्य में वे किस रोजगार को अपनाना चाहते हैं। उसमें उन्हें कितनी दक्षता हांसिल है। या वे उसमें दक्षता हांसिल करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये साफ्टवेअर बनने के बाद सारा डाटा सरकार के पास होगा केवल कुछ दिनों के अन्दर ही। यानिकि सरकार को सभी लोगों की मांगों की जानकारी एक बटन दबाते ही उपलब्ध होगी, और भविष्य में हमेंशा सरकार के पास सभी की सारी जानकारी आती रहेगी सारी मांगों की और सारे रोजगारों की यानि कितना मानव संसाधन उनके पास है और कितनी मांगें है, कितने प्राकृतिक संसाधन हैं आदि आदि सब। सरकार को पता होगा कि कुल मिलाकर सभी चीजें कितनी कितनी मात्रा में उन्हें चाहिए। कितने लोग हैं सरकार के पास रोजगार करने के लिए किस किस विभाग में और कौन क्या कार्य कर रहा है और कौन खाली बैठा है, कौन कौन से संसाधन कितनी मात्रा में है, और जो संसाधन कम मात्रा में है तो उन संसाधनों के विकल्प की जानकारी भी सरकार को रहेगी। ये सब सरकार को पता होगा। उसी साफ्टवेअर में साथ ही साथ कौन आदमी

किस कार्य में कुशल है और उन कार्यों में से वह कौनसा कार्य करना चाहता है, क्या उसकी शिक्षा का स्तर है, ये भी पता चलेगा। यदि वह किसी कारण से नहीं सीख पाया है जोकि वह सीखना चाहता था और रोजगार के रूप में उसे चुनना चाहता था, तो सरकार उसके सीखने की व्यवस्था करेगी। तब तक वह जो कार्य आता है उसे करता रह सकता है। इसप्रकार सरकार के पास पूरा डाटा होगा कि इस देश में कितनी जनसंख्या है और किस किस आयु वर्ग की, कौन कितना किस विषय में शिक्षित एवं प्रशिक्षित है। आगे आपको उस आनलाइन सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस जोकि देखने में कुछ इस तरह का होगा।

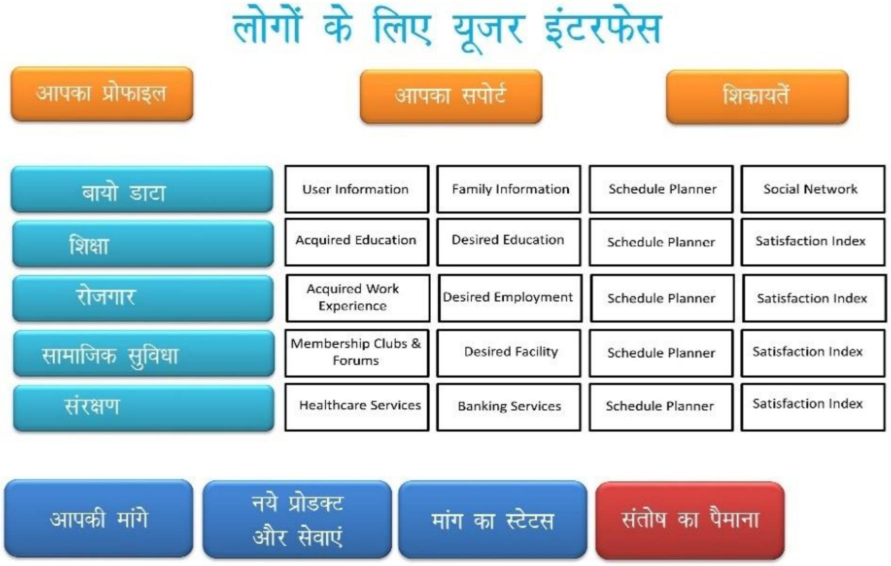

बायो डाटा	User Information	Family Information	Schedule Planner	Social Network
शिक्षा	Acquired Education	Desired Education	Schedule Planner	Satisfaction Index
रोजगार	Acquired Work Experience	Desired Employment	Schedule Planner	Satisfaction Index
सामाजिक सुविधा	Membership Clubs & Forums	Desired Facility	Schedule Planner	Satisfaction Index
संरक्षण	Healthcare Services	Banking Services	Schedule Planner	Satisfaction Index

This portal will be available on various digital platforms such as mobile app, web portal etc.

इस तरह से सरकार को कुल मांग का पता चलता रहेगा एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए कितने लोगों की, कितनी मशीनों की, कितने मालवाहकों की, कितनी मिलों की आदि किस किस क्षेत्र में आवश्यकता है जिसके द्वारा समय पर सभी की आपूर्ति की जा सके, इसकी गणना सरकार आसानी से करती रह सकेगी। सरकार इस सारी आपूर्ति को पूरा करने के लिए सभी लोगों को उनकी वरीयता एवं इच्छानुसार नियुक्त कर देगी जोकि अधिक से अधिक 5 वर्ष में उन सभी लोगों की मांगों को पूरा कर सकेगी, जिनके पास अभी किसी भी प्रकार का अभाव है। उसके बाद लगातार लोग अपनी अपनी मांग करते रहेंगे और उसी प्रकार सभी की मांगे पूरी होती रहेंगी। केवल पहले 5 वर्ष में ही अधिक भार होगा क्योंकि वर्तमान समय में आधे से अधिक जनसंख्या के पास कुछ नहीं है तो शुरू में मांगे अधिक होंगी और कार्य भी अधिक होगा। लेकिन धीरे धीरे सभी मांगे सामान्य हो जायेंगी और तबतक हमारे पास इन्फरास्टरक्चर भी हो जायेगा। तो लगभग 5 वर्षों के बाद एक साम्यावस्था आ जायेगी जहां पर सभी मांगों की आपूर्ति आसानी से होती रह सकेगी, और कार्य भी कम हो जायेगा। ज्यादातर वस्तुओं के लिए बाजार में दुकानों की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्योंकि लोगों की मांगों के अनुसार सारा सामान उनके दिये हुए पते पर कूरियर व्यवस्था के द्वारा पहुंचा दिया जाता रहेगा। केवल उन वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए बाजार में दुकानों की आवश्यकता होगी जोकि सीधे घर नहीं पहुंचाये जा सकते। जैसेकि भोजनालय, जिम आदि। इससे सड़क पर आवाजाही भी कम होगी।

और पार्किंग व्यवस्था भी खराब नहीं होगी। इस नए अर्थशास्त्र को अधिक जानने के लिए आप "संपूर्ण समाधान" का विस्तृत संस्करण पढ़ सकते हैं।

11) पैसा या मुद्रा पर आपके क्या विचार हैं?

पैसा या मुद्रा का मतलब ही हो गया, वह मूल्यांकन है एक तरह का। जब आप किसी भी वस्तु या श्रम का मूल्यांकन करते हो वहीं पर पैसा इंट्रोड्यूस हो जाता है। नहीं तो अलग से पैसे का कोई मतलब नहीं। बार्टर सिस्टम भी एक तरह का विनिमय ही होता है, वहां पर वस्तुओं को पैसे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। चाहें वस्तु विनिमय बोलो, चाहें मुद्रा विनिमय बोलो, चाहें निवेश बोलो, चाहें वेतन बोलो, चाहें खरीदना-बेचना बोलो, यह सब बाज़ार के क्रिया कलाप होते हैं। दुसरे शब्दों में आप बाज़ार चलाना चाहते हैं तो आपको मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो यह जो मुद्रा है, यह उन चीज़ों को भी विकेन्द्रीकृत कर देती है जो की केंद्रीकृत होनी चाहियें । तो यह मैनेजमेंट को ही decentralize कर देती है। और मैनेजमेंट decentralized अच्छा नहीं रहता। उसमें कुल मिलाके किसी को पता ही नहीं चलता के कहाँ कितनी मांग हो रही है, कहाँ कितनी आपूर्ति हो रही है, कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं चलता, किसी को। जिसकी वजह से सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता और यह तुक्केवाला मैनेजमेंट हो जाता है मांग और आपूर्ति का। मतलब कहीं ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी तब पता चलेगा लोगों को। बढ़ते समय या बढ़ने के पहले नहीं मालूम चल रहा है की बढ़ेगी। जब मांग बढ़ जाती है तब पता चलता है। किसी चीज़ की मांग घट जाएगी या किसी चीज़ की आपूर्ति बढ़ जाएगी तब मालूम चलेगा की ओहो यह क्या हो गया, बढ़ गया। तब जब चीज़ें हकीकत में घट जाती हैं तब बिमारी का इलाज ढूंढने का कोई मतलब नही। मतलब post-arrangement का कोई मतलब नही, pre-arrangement होना चाहिए। तो pre-arrangement के लिए ज़रूरी है की , centralized management हो।

तो मुद्रा क्या करती है की मैनेजमेंट को ही decentralize कर देती है। मतलब वहाँ एक आदमी को मालूम नहीं चलता दूसरा क्या कर रहा है, दुसरे को मालूम नहीं तीसरा क्या कर रहा है और जो सरकार बैठी है उसको मालूम नहीं, कौन क्या-क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं होता। फिर ना उसके लिए कोई योजना बना पाते हैं ना कोई मैनेजमेंट कर पाते हैं फिर भगवान भरोसे ही चलती रहती है गाड़ी और यह आप देख ही रहे हैं परिणाम से। यहां किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं तब जाकर सरकार को मालूम चलता है। तब जाके वह कोई प्रबंधन करती है, आयात करती है इत्यादि। और तब तक लोगों को बहुत नुकसान हो चुका होता, है बहुत परेशान हो चुके होते हैं, बहुत दुखी हो चुके होते है।

दूसरा इससे असमानता बढ़ेगी क्योंकि जब कोई मैनेजमेंट हो नहीं पाता तो असमानता बढ़ती है। जो कोई चतुर चालाक लोग बैठे हैं, जो कोई ऐसे पोजीशन में बैठे हैं की वह बाजार में हेर फेर कर सकते हैं, तो वह अपने हिसाब से बाज़ार नियंत्रित करते हैं, और बहुत धन इकठ्ठा कर लेते हैं एक जगह। तो सीधी सी बात है दूसरी जगह धन नहीं रहेगा। तीसरा यह है की श्रम का मूल्याङ्कन करने से जिन लोगों की आपूर्ति ज़्यादा है, उनके श्रम का मुल्य बाज़ार में बहुत कम हो जाता है। तो उनको उतनी आय नहीं हो पाती जिस से वे जीवन के सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। और ऐसे धनाढ्य लोगों

की संख्या 10 % है समाज में। तो 90% दुखी लोग रहें और 10 % सुखी लोग रहें, यह मुद्रा वाली व्यवस्था के होने से ही होता है। यह उसके परिणाम हैं, जोकि दुखदाई हैं जो की कोई नहीं चाहता। और चूँकि दुःख दुविधा कोई नहीं चाहता, और अधिक से अधिक पूँजी पे स्वामित्व ही सुख, सुविधा, संरक्षण अर्जित करने का रास्ता है ऐसी व्यवस्था में, तो पूँजी पे अधिकार के लिए मनुष्यों के बीच संग्राम शुरू हो जाता है।

12) बिना पैसे के नई आर्थिक प्रणाली कैसे काम करेगी?

यह यूँ काम करेगी क्यूंकि जीवन का उद्देश्य कोई पैसे को रखना तो नहीं है, जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। हम लोग सुखी होते हैं अपने इच्छित ज्ञान, कर्म और भोगों से। अगर हमारी इच्छा का ज्ञान हमें मिलता है, इच्छा के कर्म हमें मिलते हैं माने रोज़गार मिलता है और इच्छा के भोग हमें मिलते हैं, यानी सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं, तो उससे हम सुखी होते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है और यह सबको चाहिए होते हैं। जब सबको चाहिए होते हैं, तो यह तभी संभव है,जब सबकी समान value हो। और समान value का मतलब है किसी का मूल्याङ्कन न हो। तो जब आप किसी का कोई मूल्याङ्कन नहीं करेंगे, किसी के श्रम का निर्धारण नहीं रखेंगे तो सबकी समान value हो जाएगी। तो सब बराबरी से मांग कर सकेंगे, जो एक केन्द्रीगत प्रबंधन से पूरी होती रहेगी। तो जितनी लोगों को ज़रूरत है वह उसको पाकर सुखी हो सकेंगे। यही इसका लक्ष्य है और यह जो मैंने नया अर्थशास्त्र दिया है, उसमे कोई मूल्याङ्कन नहीं है। जब श्रम का कोई मूल्याङ्कन नहीं है तो वस्तुओं का भी कोई मूल्याङ्कन नहीं होगा, क्यूंकि वस्तुओं का मूल्याङ्कन श्रम के मूल्याङ्कन से ही आता है। तो उसमें ना कोई वेतन होगा, न कोई बैंक होगा, न कोई टैक्सेशन व्यवस्था होगी। बहुत सारे उसमें काम और भाग दौड़ खत्म हो जायेंगे। इस से एक फायदा है की कम काम में ज़्यादा सुख सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। अंततः लोग यही चाहते हैं किसी भी व्यवस्था से। तो इसलिए यह एकदम सटीक व्यवस्था है, जैसा परिणाम लोग चाहते हैं। वर्त्तमान की जो व्यवस्था है वह सटीक व्यवस्था नहीं है क्यूंकि यह वो परिणाम नहीं देती जैसा लोग चाहते हैं। वह हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं करती ।

13) संसाधन दुर्लभ हैं और मानवीय इच्छाएं अनंत हैं, आप इस कमी का प्रबंधन कैसे करेंगे?

नहीं, यह बात वास्तवीकता नहीं है। पता नहीं कहाँ से और कब यह ग़लतफ़हमी शुरू हुई, यह बात तो इतिहास में शोध करने से ही पता चलेगी। आज तक का अर्थशास्त्र अभाव के नियम पर आधारित है। बल्कि तथ्य ये है की जो अर्थशास्त्र आज तक चला आ रहा है, यह अभाव उससे पैदा हुई परिस्थितियों का लक्षण है। इसमें लगने लगता है की अभाव वास्तविकता है, क्यूंकि 90 % लोग ग़रीब जैसे जीते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो यह लगने लगता है की संसाधान सब की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम ही होगा। जबकी इसका उल्टा है कि जिस प्रकार का अर्थशास्त्र हमने अपना रखा है उसके कारण artificial अभाव पैदा हो जाता है, जिसमें मानव की सिमित इच्छाएं भी पूरी नहीं होती।

मेने जितनी खोज की है, उसमें मुझे यही पता चला की यहां सारे संसाधन एक चक्र में घूम रहे हैं, या यूँ कहें की विभिन्न चक्रों के कारण संसाधन अस्तित्वमान हैं। जैसे पानी की बात करें तो,पानी भाप बनती रहती है और बर्फ बनती रहती है और बर्फ पानी बनता रहता है और भाप बनता रहता है।

यह एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं लगातार। कुल मिलाके मतलब यह होता है की हमें जितना पानी चाहिए वह हमेशा उपलब्ध है हमें जितनी बर्फ चाहिए वह हमेशा उपलब्ध है और जितना वाष्प चाहिए वह उपलब्ध है। चूँकि यह एक दुसरे में परिवर्तित होती रहते हैं तो ओवरआल पानी की मात्रा लगभग उतनी बनी रहती है, ना तो यह कम होती है ना यह ज़्यादा होती है । बाकी प्राकृतिक संसाधनों से जितना खाना पीना और जितने दुसरे सांस्कृतिक संसाधन हम पैदा करना चाहें वह हम पैदा कर ही सकते हैं। वह हमारे हाथ में ही है।

तो जीवन का स्तर ऊंचा हो,जिसमें आपको जो ज्ञान चाहिए वह मिल जाये, जो काम चाहिए वह काम मिल जाये,जो भोग चाहिए वह भोग मिल जाये, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता की प्रकृति में कोई अभाव है। सही मैनेजमेंट और विज्ञान की मदद से सभी के लिए इंतज़ाम किया जा सकता है। और कोई एक आद चीज़ कम भी है तो उसको सही मैनेजमेंट से अधिकता में उपयोग कर सकते हैं , उसका सामाजिक वितरण कुछ इस प्रकार से हो की जब जिसको ज़रूरत हो मिल जाये, किसी एक के कब्जे में न रहे वह संसाधन। जिस से की कम मात्रा वाली चीज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। जैसे की आज कल ola, uber सर्विस दे रही हैं। इन सर्विसेज में कम गाड़ियों से, कम मानव संसाधन से ज़्यादा संख्या में लोगों को सर्विस प्रदान की जाती है। अगर व्यक्तिगत स्तर पे गाडी दी जाएगी तो वह अधिकतम समय खड़ी रहेगी और ज़्यादा संसाधनों का अपव्यय होगा। तो ऐसे मैनेजमेंट के तरीके निकाले जा सकते हैं जिस से सिमित संसाधनों से भी सभी को ऐश्वर्य में रखा जा सकता है, ज़्यादा availability कराई जा सकती है, ज़्यादा सुख पैदा किया जा सकता है। तो यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, यह कहना की संसाधन कम है और मानव की इच्छाएं अनंत है इत्यादि। चीज़ें बस पड़ी रहे 1-2 % के पास , इस्तेमाल न हो, और बाकी लोग तरसते रहे, यह असक्षम मैनेजमेंट को दर्शाता है, नाकि अभाव को।

लोगों की इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं हैं। 24 घंटे हैं , जिसमे 7-8 घंटे आदमी सोता है , 5-6 घंटे काम करता ही है , बाकी दूसरी भी गतिविधियां हैं, तो बाकी जो टाइम बचा उसमे कहाँ उसकी इतनी ज़्यादा wanting है। जो घंटे आदमी को फुर्सत में मिलते हैं ,उसमे कितनी इच्छा कर लेगा वह जो संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। एक दिन में कोई 10-12 इच्छाओं से ज़्यादा तो नहीं कर पाता। और वह भी पूरी ना हों किसी भी व्यवस्था से तो लानत है ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर के वो ऐसा बोलकर की इच्छाएं अनंत हैं बस पल्ला झाड़ लेती हैं। यह तो कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ, यह तो कोई शास्त्र नहीं हुआ। यह जो हम बोल रहे हैं की यह अर्थशास्त्र है, की यह समाज शास्त्र है, यह तो गरीबी बरक़रार रखने वाली वाली किताबें हो गयी, गरीबी बरक़रार रखने वाला ज्ञान हो गया। एक तरह का अज्ञान हो गया जो ज्ञान के रूप में परोसा जा रहा है। यह कहा जा रहा है 90 % का अभाव में जीना यथार्थ है, यह कोई शास्त्र हुआ भला। सही प्रकार का ज्ञान तो वह है जिस से यह सब सही रूप से मैनेज हो,सभी के लिए। कोई एक-आद संसाधान दुर्लभ भी है तो वह इस तरह से मैनेज हो की उसका वाज़िब उपयोग हो जाये , सब लोगों को वह available हो जाये, या कोई वैकल्पिक विधि निकाल ली जाए उस सुख को प्राप्त करवाने के लिए। तो यह बस अज्ञानता ही है ऐसा बोलना के संसाधन कम हैं और मानव की इच्छाएं अनंत हैं। कुछ भी ख़ास ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती। आप किसी भी इंसान से पूछिए , दिन में कितनी इच्छा करता है वो ? 10-12 इच्छा से ज़्यादा इच्छा नहीं करता है कोई।

उतने में उसका 24 घंटे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। और वही कुछ इच्छाएं घूमती रहती हैं ,व्यक्तित्व के अनुसार। हर आदमी की कोई 50-100 इच्छाएं होती हैं जो उसके जीवन में चक्रीय रूप में वह घुमाता रहता है। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है जीवन का ,उसकी अपनी रुचियाँ होती हैं ,और वह अनंत नहीं होती। उसके जीवन में वही कुछ विषय घुमते रहते हैं और वह कोई ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा विषयों में एकसाथ संलग्न होना संभव ही नहीं है किसी के लिए और यह मनुष्य की वास्तविकता नहीं है।

14) जब कोई प्रतिद्वंदिता (competition) नहीं होगी तो कोई नयी खोज व आविष्कार क्यों करेगा?

नयी खोज कम्पटीशन से नहीं होती है। उसका मूल कारण होता है आवश्यकता। आपने सुना होगा यह कहावत भी है की "आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है" । तो यह आवश्यकता के ऊपर आधारित है, जब आवश्यकता होती है तो खोज होती है।

दूसरा यह की जिनको खोज करने में रूचि होती है, जो वैज्ञानिक स्तर के लोग होते हैं, जिनको रिसर्च करने में मज़ा आता है, तो वह अपने हिसाब से सोच-समझ कर खोज करते रहते हैं और ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में अपडेट होता रहता है। उनको कुछ न कुछ दिखता रहता है, क्या करने से बहुत बढ़िया हो जायेगा, लोगों को और सुख सुविधा हो जाएगी, इत्यादि। यह सब वो स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं। तो इससे नयी खोज होती है।

तीसरा लोगों को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बताते हैं। वो बताते हैं तो उस ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च करे जाते हैं। तो रिसर्च आवश्यकता के आधार पे या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी समझ के आधार पे अपडेट होता रहता है। इसका कम्पटीशन से कोई लेना देना नहीं। वैसे भी कम्पटीशन उद्योगपतियों के बीच होता है, जो लोग खोज करने वाले हैं वे अपने विषय में तल्लीन रहते हैं। उनको तो उद्योगपति अपनी आवश्यकता ही बताते हैं - " ऐसा कर दो तो समाज के लिए बढ़िया हो जाएगा , बढ़िया हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकेगा "। उनका प्रोडक्ट ज़्यादा तभी बिकता है जब वास्तव में ज़रूरत होती है,लोगों को। तभी उसको खरीदते हैं,तभी उसकी मांग होती है।

तो कुल मिलाके मूल में आवश्यकता की वजह से अविष्कार होते हैं न की प्रतिद्वंदिता की वजह से। वो आप वहां सहयोगिता भी रखोगे तो तब भी आवश्यकता के आधार पर ही खोजें होती रहेंगी। आवश्यकता का प्रतिद्वंदिता से अथवा सहभागिता से कोई लेना देना नहीं। प्रतिद्वंदिता और सहभागिता एक प्लेटफार्म है जो आपको उस ढंग से उन चीज़ों को करने की जगह देता है। प्रतिद्वंदिता जो है वह ज़ोर डालने वाला तरीका है, वह नकारात्मक है जिस से आदमी को और बैचनी होती है, परेशानी होती है और चीज़ों की availability कम हो जाती है। प्रतिद्वंदिता का मतलब ही यह है की उस तरह की चीज़ों की कम availability। अगर आप abundance (प्रचुरता) कर दो तो प्रतिद्वंदिता खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो प्रतिद्वंदिता ख़राब व्यवस्था का परिणाम है और सहभागिता सही व्यवस्था का परिणाम है, इसका खोज से कोई लेना देना नहीं।

15) पूंजीवाद पर आपके क्या विचार हैं?

सीधी सी बात है , पूंजीवाद का मतलब है सारी शक्ति पूँजी में निहित कर देना। अब सारी शक्ति पूँजी में निहित कर दी तो सीधी सी बात है पूँजी जितनी जिसके पास होगी वह उतना ताकतवर होगा। तो अब हर आदमी ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए ज़्यादा पूँजी अपने पास रखना चाहेगा। और वही सब कम्पटीशन,शक्ति संघर्ष, मारा मारी,लूटपाट,अपराध पैदा होंगे जिनसे availability कम होगी। इस के कारण समाज में अशांति, दुःख, वैमनस्य यह सब चीज़ें और बढ़ने लगेंगी। तो पूंजीवाद का यह नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड इसका बहुत कम है। पॉजिटिव साइड यह समझ लो की अगर राजतन्त्र के आधार से देखें तो यह पॉजिटिव है। पूंजीवाद लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता देता है, के लोग थोड़ा अपने हिसाब से काम कर पाते हैं क्यूंकि राजतंत्र में तो राजा ही सर्वेसर्वा होता है और उसी के निर्णयों से तंत्र चलता है। तो राजतन्त्र के हिसाब से पूंजीवाद थोड़ा सा पॉजिटिव है मगर लोकतंत्र के हिसाब से पूंजीवाद नेगेटिव है।

16) साम्यवाद पर आपके क्या विचार हैं?

साम्यवाद तो केवल एक कांसेप्ट ही है,वह कभी कहीं आया नहीं पूर्णतया। वह जब भी आया वह समाजवाद के रूप में ही आया है। साम्यवाद का मतलब रहता है - समतामूलक वर्गविहीन समाज याने के जो संसाधन है उसपे सबका बराबर का अधिकार है और साम्यवाद उसमें बोलता है की उसे किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई केन्द्रीगत मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो की एक असंभव वाली बात है। क्यूंकि कोई भी एक व्यवस्था आएगी तो उसमें मैनेजमेंट तो होगा, केन्द्रीकरण तो होगा। कोई भी व्यवस्था बिना केन्द्रीकरण के संभव नहीं। अगर आप उसे उन चीज़ों में विकेन्द्रीगत करेंगे जो मैनेजमेंट पार्ट है, तो वैसा ही हो जायेगा जैसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन छोटे -छोटे राज्य भी अपने आप में एक इकाई हो गए। उतने भाग में मैनेजमेंट का फिर से केन्द्रीकरण हो जायेगा। पूरा विकेन्द्रीकरण का एक मतलब तो यह होगा के एकदम हर आदमी अपनी व्यवस्था ख़ुद करे, तो यह तो संभव नहीं। दूसरा यह एक ऐसी हवाई कल्पना सी है जो बस कह रही है सभी समाज जनित सुख सुविधाओं पे सब बराबर के हक़दार हैं लेकिन स्पष्ट बता नहीं रही यह प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे होगा। साम्यवाद कहता है अधिकार और कर्तव्य में आत्मार्पित सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होगा। परन्तु यह कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं। तो यह एक यूटोपियन कांसेप्ट रह जाता है। तो साम्यवाद आ नहीं सकता और जब भी आएगा समाजवाद के रूप में ही आएगा।

17) क्या आपका मॉडल साम्यवाद का दूसरा संस्करण नहीं है? यह मॉडल समाजवाद और पूंजीवाद से कैसे भिन्न है?

जी संपूर्ण समाधान व्यवस्था साम्यवाद का न दूसरा संस्करण है और न पहला। पहली बात यह है की साम्यवाद एक ऐसा कांसेप्ट है जिसको समाज में प्रस्तावित किये हुए काफी समय हो गया है और वह कहीं भी दुनिया में आ नहीं पाया। यह केवल लोगों के ख़्वाब में ही रही बात है। वह कभी भी ज़मीन पर आज तक आ नहीं सका और वह संभव भी नहीं है आना। जिस तरह साम्यवाद feasible नहीं और धरातल पर उतर नहीं सकती उसी तरह शुद्ध पूंजीवाद (ideal free market) भी वास्तविक नहीं और केवल एक कल्पना है। शुद्ध पूंजीवाद का मतलब है एक पूर्ण रूप से अनियंत्रित बाज़ार।

जब के संपूर्ण समाधान एक नया कांसेप्ट है, जो मूल से अलग है,और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है की आर्थिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस कैसे होगा। संपूर्ण समाधान एक ख़्वाब की तरह प्रस्तुत नहीं है बल्कि स्पष्ट बताता है कैसे आदर्श स्थिति प्राप्त होगी, जो के समझना आसान है। तो यह एक feasible model है और इसका साम्यवाद से समाजवाद से और पूंजीवाद से दूर तक लेना-देना नहीं।

मौलिक रूप से अंतर यह है की संपूर्ण समाधान व्यवस्था में मैनेजमेंट 100% केंद्रीकृत है और जो पावर है वह 100 % विकेन्द्रीकृत है। जबकि समाजवाद इस मामले में एक अस्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। समाजवादी व्यवस्था प्रस्तावित करता है धन-सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियन्त्रण के अधीन होने चाहियें। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी सम्पत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। उसकी एक बुनियादी प्रतिज्ञा यह भी है कि सम्पदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथों में होना चाहिए।

अगर हम सोशलिस्ट कमांड इकॉनमी (सेंट्रली प्लांड इकॉनमी) की बात करें तो उसमे मैनेजमेंट और पावर दोनों सरकार में कुछ लोगों के हाथों चली जाती है और लोगों की स्वतंत्रता का हनन होता है, और ऐसा होना उस के अर्थशास्त्र के ढाँचे में निहित है। तो यह तो समाजवाद नहीं हुआ। यह तो एक तरह की राजशाही हो गयी। अगर हम सोशलिस्ट मार्किट इकॉनमी या फिर मिश्रित इकॉनमी की बात करते हैं तो इसमें पावर पूंजीपति और सरकार के हाथ चली जाती है। बस पांच साल में एक बार जनता को मत डालने का अधिकार होता है। इसके अलावा लोगों का जीवन पूंजीपति और सरकार की मिली भगत से चलता है। इसमें भी धन कुछ के हाथों में इकठ्ठा हो जाता है। तो यह भी तो नाम मात्र का समाजवाद हुआ। इसमें कहाँ दिख रहा है की समाज प्रथम हो रहा है? कहाँ से समाज का भला हुआ जा रहा है?

यह अलग बात है की मिश्रित इकॉनमी का मॉडल एक तरफ कमांड इकॉनमी के मॉडल से बेहतर है और दूसरी तरफ सामंतवाद और राजतन्त्र के ढांचों से बेहतर है। इस मिश्रित इकॉनमी में मैनेजमेंट का थोड़ा केन्द्रीकरण और थोड़ा विकेन्द्रीकरण होता है। मिश्रित मॉडल यह बोलता है की स्टेट तो चाहिए मगर पूर्णतः नहीं। तो यह एक मध्यम स्तर की व्यवस्था हो जाती है। माने कुछ ठीक है और कुछ ख़राब। तो उसमें बाज़ार भी रहेगा और सरकार का कण्ट्रोल भी रहेगा, तो न ठीक से पूंजीवाद हो पाता है न ठीक से समाजवाद। ठीक से किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। कुछ मालूम नहीं चलता कौन किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, कौन क्या कर रहा है और ऐसा लगता है गाड़ी भगवान भरोसे चल रही है। ऐसे मॉडल में विभिन्न ग्रुप्स बनने लगते हैं और जब उनके हित परस्पर संघर्ष में आते हैं, उनके बीच फिर वही मारधाड़, अशांति और सुखों की unavailability का उदय होता है। तो इसलिए यह भी कोई समाधान नहीं। मूल में अब तक के यह सारे मॉडल कुछ ही लोगों का ऐश्वर्य का जीवन जीने का मौका दे रहे हैं, सभी को दे पाएं ऐसी उनकी उद्घोषणा भी नहीं, न ही डिज़ाइन। अब अगर मुट्ठी भर लोग ऐश्वर्य पाएंगे तो ऐसी व्यवस्था लोगों के किस काम की। यह तो बस एक मजबूरी वाला जीवन प्रदान करेगी, जो दिख ही रहा है। जबकि संपूर्ण समाधान की उद्घोषणा है - सभी सुखी हों -ऐसी व्यवस्था - सभी को इच्छित जीवन मिले - ऐसी व्यवस्था।

एक और बात है जिससे आपको पता चलेगा की संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो है, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद से सैद्धांतिक रूप से भी अलग क्यों है। समाजवाद और साम्यवाद में समाज प्रथम है, व्यक्ति और परिवार का स्वार्थ गौण हैं। पूंजीवाद में व्यक्ति प्रथम है, उसका अपने स्वार्थ के लिए काम करना उचित माना जाता है। जबकि संपूर्ण समाधान में व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरी समष्टि को यथा उचित स्थान मिला है जिससे की मनुष्य चारों स्तरों में पूर्णतः सुखी हो, वह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सामष्टिक स्तर पर अपने आप को संतुष्ट पाए। व्यवस्था आने पर न कोई अमीर होगा न गरीब, सब अपनी इच्छा का जीवन जी रहे होंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा की कोई इस तरह से अमीर होगा की संपत्ति होते हुई भी चिंतित होगा और कोई गरीब होकर परेशां होगा। पूर्व की वयवस्थाएँ सभी तलों पर मनुष्य को सुखी करने के लिए सक्षम नहीं हैं। आप देख सकते हैं, यह सब मूल में बड़े अंतर हैं और इस से सारे अंतर आ जाते हैं।

साम्यवाद के प्रतिपादकों का कहना भी यही है की साम्यवाद ,समाजवाद की उन्नत अवस्था को अभिव्यक्त करता है। लेकिन यहां पर वे समाजवाद से साम्यवाद तक पहुंचने में वैचारिक रूप से एक कूद मार देते हैं। बस यही कहते हैं की means of production काफी बढ़ गए होंगे। यह बता के नहीं दिया जाता की लोगों के विभिन्न इच्छाओं के लिए , बदलते इच्छाओं के लिए , प्रबंधन कैसे होगा। यह बात स्पष्ट नहीं होती। साम्यववाद के दर्शन में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति केंद्र में नहीं है। यह इस बात से भी जाना जा सकता है जब वे कर्तव्य और अधिकार के बारे में बात करते हैं। जहाँ समाजवाद में कर्तव्य और अधिकार के वितरण को '**हरेक से अपनी क्षमतानुसार, हरेक को कार्यानुसार**' के सूत्र से नियमित किया जाता है, वहीं साम्यवाद में '**हरेक से क्षमतानुसार, हरेक को आवश्यकतानुसार** सिद्धांत का लागू किया जाता है। तो आवश्यकता अनुसार मतलब क्या - एक कमरे का घर, दो जोड़ी कपडे और थोड़ा खाना ?

जबकि संपूर्ण समाधान का कहना यह है की – **सभी के लिए जीवन इच्छा अनुसार** । संपूर्ण समाधान में मनुष्य की **इच्छाएं केंद्र में हैं**। तो दार्शानिक रूप से, मूल में ही अंतर है। इसलिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था में अर्थशास्त्र अलग है, दर्शन शास्त्र अलग है, पारिवारिक मॉडल भी अलग है, सामाजिक मॉडल भी अलग है, पोलिटिकल मॉडल भी अलग है, शिक्षा का मॉडल भी अलग है, सबकुछ अलग है।

18) यदि लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, तो वे काम क्यों करेंगे? हम गुणवत्ता और दक्षता कैसे बनाए रख सकते हैं?

जैसा की मैंने किताब में भी उल्लेख किया है, आर्थिक रूप से सुरक्षित केवल बच्चे, बुज़ुर्ग और बीमार लोग हैं। बाक़ी तभी हैं जब वो कोई काम करेंगे। जो 25-50 उम्र के स्वस्थ लोग हैं, अगर वो कोई रोज़गार नहीं करते हैं, तो वे आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसा है नहीं जैसा सवाल में पूछा जा रहा है। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए व्यवस्था में कोई न कोई काम अनिवार्य होगा।

गुणवत्ता और दक्षता इसलिए संभव है क्यूंकि सभी अपनी रूचि और योग्यता के हिसाब से काम कर रहे होंगे। जब यह व्यवस्था पूरी तरह से स्थित हो जाएगी तो लोगों को उनकी अभिरुचि अनुसार ही

काम मिलेगा और इच्छा का काम करना सबको पसंद आता है। जब काम करने में मज़ा आता है तो हर आदमी अपने आप ही बेस्ट देता है। उसके अंदर से जितना भी बेस्ट निकल सकता है वह qualitative वस्तु व सेवा के रूप में परिणित होगा।

दूसरा यह है की व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार एक स्वीकार्य production target को हामी देगा। व्यवस्था उसे productivity बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर रही। वह तो एक दिन के काम को 2 घंटे में करे या 6 घंटे में यह उसके ऊपर है। व्यवस्था कोई बंधा-बंधाया स्पीड नहीं फिक्स कर रही काम को करने का । अंदाज़न सभी 4-5 घंटे का काम करेंगे। हर काम करने वाले व्यक्ति का output तय होगा जो की धीरे धीरे करने पर भी प्राप्त करना संभव होगा। तो सभी अपनी स्पीड के अनुसार उसे कर के देंगे। व्यवस्था को फाइनल output और उसकी quality से मतलब है। आप कितनी तेज़ी से या धीरे करते हैं, इस से मतलब नही। आपको अपने पूर्व निर्धारित,स्व स्वीकृत output target को एक समय सीमा के अंदर मीट करना है बस। इस से यह होगा की कोई किसी पर पुलिस की तरह निगरानी नहीं रख रहा होगा। लोगों को भय और डंडे के ज़ोर पे काम नहीं करवाया जा रहा। लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे होंगे और अपना बेस्ट स्वाभाविक रूप से दे रहे होंगे और हर काम का quality check विभिन्न stages में होता रहेगा।

तीसरा यह है की जनता का feedback लगातार आता रहेगा । पावर चूँकि decentralize है तो जब जनता उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगी और अगर वह qualitative नहीं होगा तो वहां से उसका final review आ जायेगा। उसका review यदि negative आयेगा तो उस आदमी, team या department पर सवाल खड़ा होगा जिसने भी बनाया। तो जिसने भी बनाया उस से पूछा जाएगा क्या दिक्कत हुई , और root cause analysis के बाद वह दिक्कत दूर करी जायेगी और ज़रूरी measures लिए जायेंगे ताकी end user संतुष्ट हो और वह दिक्कत फिर से न हो। इस तरह से इसमें quality control होता रहेगा।

19) कोई भी जोखिम भरे काम अथवा हीन काम करने के लिए क्यों तैयार होगा?

जोखिम वाले काम या हीन काम तो बचेंगे नहीं। इस नए अर्थशास्त्र में कोई निवेश तो है नहीं जो डूब जायेगा। यह एक दम zero risk वाली अर्थव्यवस्था है। इसमें सबकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और सबका मूल्य समान है, तो कोई काम हीन नहीं देखा जायेगा। दूसरा मशीनरी का भरपूर उपयोग है। तो कोई काम कठिन भी नहीं है। तीसरा कठिनाई जो है आपके रूचि के आधार पर होती है। अगर आपको आपके रूचि का काम दिया जाये तो वह सरल ही होता है और आपके रूचि के इतर कोई काम दिया जाये तो वह कठिन ही होता है। तो यह कठिनता और सरलता psychological है। नयी व्यवस्था में जोखिम में डालके मजबूरन कोई काम नहीं है। यह पूरा का पूरा बिना जोखिम वाला समाधान है जिसमें आप अपनी रूचि, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा आदि के आधार पर ही कोई काम चुनेंगे। तो उसमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। अभी के अर्थशास्त्र में सरकार और प्राइवेट कंपनियां पैसे बचाने के चक्कर में कई जोखिम वाले काम पैदा कर देती हैं, जिसमें काम करने वाले की safety पे पूरा पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। पर्याप्त अनुसंधान और तकनिकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्यूंकि वह cost efficient नहीं होगा। और फिर अव्यवस्था से भी विषमता पैदा होती है

, जिसमें कई सारे खतरे पैदा हो जाते हैं। लेकिन नयी व्यवस्था में यह मजबूरी नहीं होगी, इसलिए हर काम सोचे समझे planning से होगा जिसमें risk factor लगभग शुन्य होगा। और जरा मरा कुछ कठिनाई रह जाएगी तो वैज्ञानिक उसके लिए खोज करके उसको सरल कर देंगे।

20) आप चार प्रकार की मानव व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं; इस वर्गीकरण और इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा बताएं?

चार प्रकार के जो मानव हैं वो ऐसे समझने की दृष्टि से है क्यूंकि रोज़गार का वर्गीकरण है। चूँकि काम अलग अलग तरह के होते हैं और हर काम को करने के लिए अलग-अलग पात्रता, क्षमता, योग्यता, रूचि आदि की ज़रूरत पड़ती है तो इसके आधार से हमें यह समझना होता है की कौन आदमी किस योग्य है, क्या पात्रता है, क्या रूचि है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। नहीं तो कर्मों का निर्धारण नहीं हो पायेगा और कर्मों का निर्धारण नहीं हो पायेगा तो उस कर्म में जो quality आनी चाहिए वो नहीं आ पायेगी। अगर quality नहीं आ पायेगी तो हमें उच्च quality के भोग नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए यह ज़रूरी है के हम जानें कितने प्रकार के लोग होते हैं, और उसी प्रकार से शिक्षा को डिज़ाइन किया जाए, उसी प्रकार से लोगों को मालूम भी हो, उनको पता चले के वे किस वर्गीकरण में आ रहे हैं ताकि उनको अपने पसंद का ज्ञान, पसंद का रोज़गार, पसंद का रहन सहन, पसंद के सुख सुविधाएं, पसंद के सम्बन्ध इत्याद्दी का चुनाव करने में सुहूलियत हो। तो व्यक्ति जो चुनाव करता है उसमें उसको सहायता के लिए वर्गीकरण को पेश किया गया है। ताकि सभी अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपने इच्छित सुखों तक सुगमता से पहुंच पाएं।

इस वर्गीकरण का असमानता से कोई लेना देना नहीं है, इस वर्गीकरण का यह कतई मतलब नहीं की एक आदमी महान होता है और दूसरा तुच्छ होता है, यह बिलकुल नहीं है। इसमें सारे लोग बराबर हैं। इसमें यह नहीं है की एक आदमी दुसरे आदमी के सामने झुक के नमस्कार करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 25 साल की उम्र हुई तो हर व्यक्ति बराबर है एक तरह से। उनमें कोई भी ऊँचा या नीचा नहीं है किसी भी तरह से, परस्पर वे कोई भी हों, चाहें वो बाप बेटा ही क्यूँ न हों। बेटा या बेटी 25 साल के हो गए तो वे एक स्वतंत्र इकाई हैं। पिता के, माता के, दादा के, दादी के या किसी के भी समकक्ष की ही स्तिथि होगी उनकी। अगर वे चाहें तो बुजुर्गों को नमस्कार करते रहे उनको इच्छा है तो, संपूर्ण समाधान व्यवस्था के अनुसार वहां पर बराबरी का ही अभिवादन होना चाहिए। अलग से नतमस्तक होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यूंकि उस व्यवस्था में सब बराबर के नागरिक हैं और सब रूप से समानता है उनके बीच। उनके सारे अधिकार बराबर के हैं। जब तक 25 साल का कोई नहीं हो जाता तो यह माना जाता है की वह अभी विभिन्न चीज़ों में develop हो रहा है, कई चीज़ों में अभी उनको समझ नहीं होगी तो वहां निर्देशन की ज़रूरत है ताकि वो कुछ ऐसा न करें जिस से उसको और दूसरों को दुख उठाना पड़े।

तो जैसे -जैसे बड़े होते जायेंगे तो वैसे वैसे उनकी स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी और जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी, इस प्रकार से व्यवस्था है। 25 साल के बाद में पूर्ण स्वतंत्रता है जैसे किसी को भी होगी। तो इस प्रकार का यह वर्गीकरण है, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो यह व्यवस्था की दृष्टि से विकसित गया है, अधिकार के दृष्टि से कोई अंतर नहीं विभिन्न मनुष्यों में।

Political model

21) लोकतंत्र के मौजूदा मॉडल और लोकतंत्र के नए मॉडल के बीच मुख्य अंतर क्या है?

मुख्य अंतर यह है की जो मॉडल अभी चल रहा है उसमें लोगों को चुनाव करने की जो शक्ति है या सत्ता की जो पावर है, वह पांच साल में एक बार, 5 मिनट के लिए मिलती है, जिसमें वो किसी और को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, किसी और को अपनी पावर पकड़ा देते हैं। वहां दोनों तरह की पावर वह पकड़ा देते हैं, एक तो पावर है के वो जनता के behalf पर मैनेजमेंट करेंगे, नीति नियमों का निर्धारण करेंगे और दूसरा की पसंद / नापसंद की पावर भी वो उनको दे देते हैं, के भाई आप ही जानो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें पसंद आना चाहिए क्या नहीं, वह भी आप ही निर्धारण करो। तो यह दोनों तरह की पावर हम उनको दे देते हैं।

जबकि संपूर्ण समाधान का जो राजनैतिक मॉडल है उसमें सत्ता की पावर 24 घंटे जनता में निहित रहने वाली है। किस प्रकार से - के उसमें दो तरह की पावर्स हैं, एक पावर है जो कर्म का प्रतिनिधितव करती है। माने जो नेता हैं वो नीति निर्धारण , माने वो नीतियां बना सकते हैं, क्यूंकि इन्हें उस प्रकार की समझ होती है, उस प्रकार के वो ज्ञानी होते हैं, उस प्रकार के वे expert होते हैं। तो यह जो कर्म है, ये उनको गया है। यह एक तरह से पावर नहीं है। तो वो नीति नियमों का निर्धारण कर सकते है , बना सकते हैं और वह नीति नियन बना के वे 3 महीने public forum में रहेंगी। Public forum में यदि 10% नेगेटिव वोट उनके नहीं जाता है , तब फिर ये मान लिया जायेगा की , हाँ लोगों को स्वीकार्य है ये नीति, तो फिर वह नीति लागु हो जाएगी। और वह नीति लागु होने का बाद फिर भी उसकी voting line हमेशा खुली रहेगी। अगर कभी भी उस नीति की वजह से कोई नुकसान होता है किन्हीं को , तो भी यदि 10 % negative voting होगी तब भी वो नीति जो है निरस्त हो जाएगी। इस प्रकार से सारी पावर जनता में हमेशा निहित रहेगी, जोकि आज के सिस्टम में नहीं है।

अपनी पावर देके और 5 साल के लिए हम लोग बिना पावर के हो जाते हैं। अब वो लोग ही हमारे सारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। नीति नियम भी वही बनाते हैं और लागू भी वही करते हैं, हमें क्या पसंद आएगा नहीं आएगा इसका भी वही सोचते हैं, हमसे पूछते तक नहीं पांच साल तक। तो कुल मिलके हमारे पास कोई पावर नहीं रहती, हम अपने हाथ कटा देते हैं। और उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं की पोलिटिकल सत्ता और जो अमीर बिज़नेस पावर्स हैं मिलकर एक नेक्सस बना लेते हैं। और वे अपने हिसाब की नीतियां बनाते हैं और ऐश्वर्य की ज़िन्दगी जीते हैं। अपनी तनखायें दो से पांच लाख तक कर रखी हैं। अब आप ही बताइये जिस देश में नागरिक को रोज़गार तक नहीं मिलती और जिनको है भी तो 8-10000 रुपये की तन्खा मिलती है, तो किसी भी नेता को 2-2.5 लाख तन्खा और दुसरे benefits लेने का क्या अधिकार है? यह अधिकार उनको जनता ने तो नहीं दिया। यह अधिकार तो उन्होंने खुद ले लिया संसद में जाके। तो यह तो ठीक बात नहीं है न फिर। यह तो फिर ऐसे हो गया, घर में जो अभिवावक होता है, माने जो पिता होता है, वह अपने लिए सारी सुख सुविधाएं रखे, खुद फल खाये, जूस पिए, दारु पिए, मतलब जैसा जीवन जीना चाहे जिए जबकि बच्चे हैं, पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं, उनको केवल दो रोटी दे, किसी को आधी रोटी दे दे, यह कोई बात है भला? इसी प्रकार यदि सरकार किसी को 2 रुपये किलो चावल दे, यह कोई बात है भला? यह कोई व्यवस्था होती है, इसको व्यवस्था बोलते हैं? यह कोई लोकतंत्र है? या लोकतंत्र के नाम पर मज़ाक है? लोक

तंत्र क्या यह तो लूट तंत्र जैसा हो गया, यह तो भर्राशाही है। इसलिए इसको दल तंत्र कहा गया है। एक दल के पास ही ताकत रहती है। बस हर पांच साल में लोग किसी एक को वोट देने के लिए मजबूर हैं। और यह वो मजबूर हैं! ऐसा नहीं है की वो नहीं चाहें किसी दल को देना। उन्हें किसी न किसी दल को देना ही पड़ेगा। सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, किसी दल के पास ही हमेशा ताकत रहेगी, तो यह दल तंत्र है, यह लोकतंत्र नहीं है। हम लोग जो प्रस्ताव रख रहे हैं वह, पूर्ण लोकतांत्रिक है, उसमें 24 घंटे , सत्ता की जो पावर है, हमेशा जनता के पास ही रहने वाली है। जनता हर समय निर्धारण करेगी की वह किसी को रखेगी या नहीं। अंतिम रूप से जनता ही निर्णय करेगी कोई नीति , नियम उसे स्वीकार्य है या नहीं। नेता का काम है केवल अपने expertise या ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए , जनहित में अपना best प्रस्ताव रखे।

22) संक्षेप में बताइये, आपका नया पोलिटिकल मॉडल क्या है?

नए political model में जो लोग खड़े होंगे नेता बनने के लिए, उनकी परीक्षा होगी। उनका selection exam होगा election से पहले। जैसे IAS वगैरह के परीक्षा होते हैं, वैसे leadership वगैरह के लिए भी परीक्षा होंगे, उन परीक्षा में जो लोग pass करेंगे, तो उस आधार से वही लोग चुनाव के उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन कर सकेंगे। सभी लोग नहीं, नई तो कोई भी करता रहेगा, जिसको उस विषय का ज्ञान नहीं। यह परीक्षा किस आधार से नेतृत्व क्षमता को जांचेगा, इसके लिए आपको विस्तार से मनुष्य चेतना और उसके वर्गीकरण को समझना पड़ेगा, जोकि मैंने अपनी किताब में समझाया है। दूसरा, इसमें एक मुख्य चुनाव आयोग होगा जो सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। इस व्यवस्था में दलों का कोई अस्तित्व नहीं होगाा। चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हमें प्रशाशनिक क्षेत्रों के विभाजन को समझना होगा। लगभग २-५ लाख आवासों वाले सभी सुविधाओं से सम्पन्न एक क्षेत्र को नगर की संज्ञा दी जायेगी। और धीरे-धीरे पूरे भारत में इसी प्रकार के नगर स्थापित किये जायेंगे। सभी क्षेत्रों में एकजैसी ही सुविधाएं एवं संरक्षण होगा। 20 नगरों को मिलाकर 1 जिला माना जायेगा। इसी प्रकार 20 जिलों को मिलाकर एक राज्य माना जायेगा। और 20 राज्यों को मिलाकर एक देश माना जायेगा। और ऐसे सभी देशों को मिलाकर एक विश्व माना जायेगा।

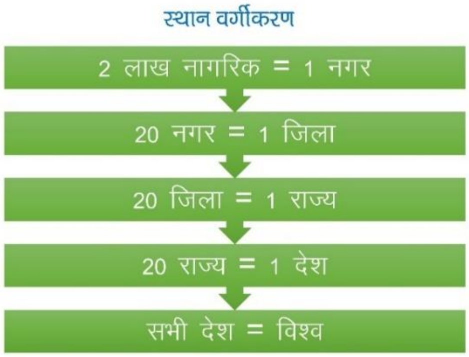

नगर स्तर पर चेतनात्मक लोग चुनाव के लिए अधिक्रत हो सकेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में केवल 10 अधिक योग्य आवेदकों को ही चुनाव में उतारा जायेगा। जिनमें से जनता 5 नेताओं का चुनाव करेगी। उदाहरण के लिए 200,000 तक की जनता के लिए 10 में से 5 नेताओं का अर्थात् एक नगर के लिए

5 नेताओं का चयन होगा। केवल नगर स्तर के नेता जनता द्वारा चुने जायेंगे। फिर इन चुने हुए नेताओं के द्वारा जिला स्तर के 5 नेताओं को चुना जायेगा। फिर जिला स्तर के नेताओं के द्वारा राज्य स्तर के 5 नेताओं को चुना जायेगा। और इसी तरह राज्य स्तर के नेताओं द्वारा देश के 5 नेताओं को चुना जायेंगा। और अंत में इसी प्रकार सारे देश के नेता मिलकर विश्व के लिए 5 नेताओं को चुनेंगे या प्रत्येक देश से एक नेता विश्व सरकार के लिए चुना जा सकता है। हर स्तर पर 5 में से 1 मुख्य और 4 सहायक नेता होंगे।

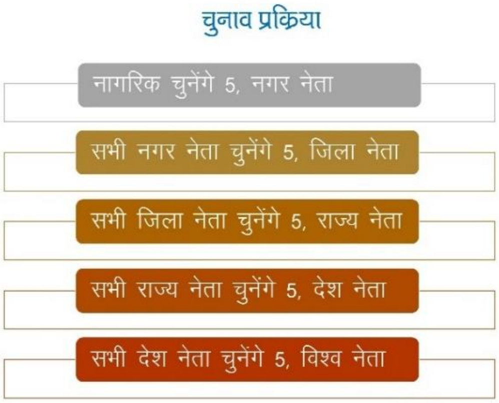
चुनाव प्रक्रिया
नागरिक चुनेंगे 5, नगर नेता
सभी नगर नेता चुनेंगे 5, जिला नेता
सभी जिला नेता चुनेंगे 5, राज्य नेता
सभी राज्य नेता चुनेंगे 5, देश नेता
सभी देश नेता चुनेंगे 5, विश्व नेता

सामान्यतः सभी नेताओं का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। इस प्रकार करने से नेताओं का चुनाव नीचे से उपर की ओर होगा और व्यवस्था उपर से नीचे की ओर होगी। अर्थात मुख्य संविधान विश्व स्तर के नेताओं द्वारा लिखा या संशोधित किया जायेगा। जिसके अनुसार सभी स्तरों पर व्यवस्था होगी। विश्व सरकार अपने स्तर के कार्यों को करेगी एवं देशों की सरकारां को आवश्यक दिशानिर्देश देती रहेगी आवश्यकतानुसार और उनके कार्यों का निरीक्षण करती रहेगी। देश सरकार अपने कार्यों के साथ साथ राज्य सरकारों को दिशानिर्देश देगी और उनके कार्यां का निरीक्षण करेगी। इसी प्रकार ग्राम सरकार तक चलेगा। तो चुनाव नीचे से उपर और शासन उपर से नीचे होगा। इससे सदैव ही शक्ति का संतुलन बना रहेगा। अंतिम नियंत्रण सदैव जनता के पास ही बना रहेगा।

इस नयी व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य अपने सभी सुखों के लिए सदैव ही अपनी satisfaction rating देते रहेंगे। यदि कोई भी मनुष्य कभी भी व्यवस्था के कारण कोई दुख पाता है तो वो अपनी रेटिंग के द्वारा सूचित कर सकेगा, जिसे सभी इंटरनेट पर जब चाहे देख सकेंगे। सरकार को तुरंत ही उसके दुख का कारण दूर करना होगा। इसी मानक के आधार से सरकार के कार्यों की स्थिति समझी जा सकेगी कि सरकार कितनी सफल हुई। तो जब भी लोग व्यवस्था के साथ interact करेंगे और तो वो अपनी satisfaction rating वहाँ पर दे सकेंगे। यह 0-10 तक का scale होगा जिसमें 5 मध्य पॉइंट है। 5 rating का मतलब आप satisfied हैं। 5-के ऊपर जितनी बड़ी रेटिंग देंगे यह माना जायेगा की उस प्रोडक्ट या सर्विस से आप की प्रसन्नता उतनी बड़ी है। उसी तरह पांच के नीचे आप जितना जायेंगे, उसका मतलब आप उतना नाखुश है। अगर आप कोई रेटिंग नहीं देते तो यह माना जायेगा की default rating 5 है, आपकी तरफ से। इन satisfaction ratings से नेताओं का ,

उनके साथ काम करने वाले दुसरे officials का performance rating निकाला जायेगा। सभी कर्मचारियों का रेटिंग निकाला जायेगा। एक डिपार्टमेंट ख़ास तोर पर इसी के लिए होगा जो हर satisfaction rating से हर पदवी पर बैठे व्यक्ति की performance rating की गणना करे, एक algorithm के ज़रिये। इसके लिए हर नीति, नियम, निर्णय और उस से जुड़े output की mapping पहले से ही करी जाएगी। अगर performance rating एक स्तर से नीचे चली जाती है तो उस नेता के मैनेजमेंट पर, उसके नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो जायेगा। तो इन ratings की वस्तुतः स्तिथि को देख कर वह नेता तो पहले से ही मामले को sort out करता रहेगा और अगर नहीं कर पाता है तो वहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो जायेगा। फिर ऊंचे level के नेता मिलके उस समस्या को address करेंगे, और जांचेंगे क्या समस्या है, क्यों समाधित नहीं हो रही इत्यादि। Negative performance पर उस व्यक्ति की पदवी चली जाएगी और उसके समक्ष दुसरे उपयुक्त कर्म की प्रस्तावना रख दी जायेगी। तो जिनकी भी negative performance rating निकलेगी वे सभी प्रश्न के दायरे में आएंगे। तो इस प्रकार से प्रशाशन चलेगा , जिसमें की जनता के पास पावर रहेगी। जनता अपने satisfaction rating से पदों को control कर रही होगी ।

23) आप बोलते हैं कि नेताओं को चयन परीक्षा और फिर चुनाव से गुज़रना होगा। किसी परीक्षा द्वारा किसी व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता का परीक्षण कैसे संभव है?

यह यूँ संभव है की उस व्यक्ति में जांचा जायेगा की नेतृत्व की खूबियां हैं की नहीं। इसके लिए परीक्षा से सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। परीक्षा से तो किसी के भी क्षमता का आंकलन किया जा सकता है जैसे आज बहुत सारी क्षमताओं का आंकलन किया ही जाता है। जैसे कोई व्यक्ति software बना सकता है की नहीं ये जांचने के लिए उसे software exam देना पड़ता है। उससे software सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाते हैं, code लिखवाये जाते हैं और उसके लिखे code को test करते हैं। अगर वह code run कर रहा है तो यह समझा जाता है की उसे coding आती है। इसी प्रकार leadership exam भी है। कई तरह के सवाल होंगे जिसमे विभिन्न scenarios प्रस्तुत किये जायेंगे और ये देखा जायेगा की उन परिस्थितियों में उन समस्याओं के समाधान हेतु परीक्षार्थी किस प्रकार की नीतियां बनाता है व निर्णय लेता है। यह देखा जायेगा की उस व्यक्ति को जीवन दर्शन के बारे में और व्यवस्था के विभिन्न आयामों के बारे में कितनी समझ है। नेतृत्व के लिए जिन विषयों का ज्ञान होना अनिवार्य है उसमें उस परीक्षार्थी की कितनी पकड़ है यह examination द्वारा जांचा जायेगा, जिससे यह तय होगा की नीति निर्धारण करने में वह व्यक्ति सक्षम है की नहीं। अगर वह उस परीक्षा को pass करता है तो उसे election में खड़े होने के लिए certification मिल जायेगा ।

24) नेतृत्व की आपकी परिभाषा क्या है?

जो भी काम होते हैं, हर काम का एक अपना फ्रेम होता है, एक दायरा होता है। दायरे से यहां मतलब है के उसमें किस तरह के मानव संसाधन होंगे, क्या उनके skills होंगे, किस तरह के systems होंगे, क्या- क्या विषयों का ज्ञान चाहिए होगा, किस तरह के शोध का सहारा लिया जायेगा, किन लोगों पर उस काम का असर पड़ेगा, इत्यादि। हर एक बड़े फ्रेम को चलाने के लिए नेताओं की ज़रूरत पड़ती है , और उस फ्रेम के अंतर्गत जो भी सारी व्यवस्थाएं आती हैं, तो उन सारी व्यवस्थाओं की समझ जो व्यक्ति रखता हो और उनको direct करने की जो क्षमता रखता हो, उसको नेता कहेंगे। उसको पता

हो की कहाँ क्या बदलाव करने से कहाँ क्या असर पड़ेगा, वहां अगर कोई समस्या उठ रही है तो कहाँ से उठ रही है माने उसके तार कहाँ से जुड़े हैं, उसको वह देखने में सक्षम होता हो, और क्या अंतर करने से ठीक हो जायेगा, और वह यह भी जान पाए कौन सी समस्या उसके specialization के बाहर की है, ऐसी क्षमता उसमें रहती है, तो वह नेतृत्व के लिए योग्य है। जो उस दायरे में सारी देख रेख कर पाता है, उतने फ्रेम को वह दिशा दे पाता है, उतने फ्रेम को अच्छे से चला पाता है, कोई समस्या उठने वाली है तो भांप पाता है और तुरंत उसके लिए सही कदम उठा पाता है, उतने फ्रेम से जितने लोग सम्बंधित हैं उन सबको संतुष्टि दे पाता है, तो वह नेता है। यह उसकी क्षमताएं होती हैं, यह सारे उसके लक्षण हैं और ये उसके काम में performance से पता चलेगा। यदि उसका performance संतोष जनक है तो वह व्यक्ति फिर उस योग्य है। हो सकता है वह किसी ढंग से exam को पास कर जाए, कुछ भी कर के, लेकिन उसके performance से final check हो जायेगा। तो यहां पर double check है, एक जब वो परीक्षा देगा, दूसरा जब वह काम करेगा और उसकी performance rating आएगी।

25) आपके अनुसार स्वतंत्रता क्या है?

मेरे अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है आप जैसा जीना चाहते हैं अगर वैसा जैसा जीवन जी पा रहे हैं , तो यह आपकी ultimate freedom है। क्यूंकि freedom का मतलब है के हम जो education चाहते हैं वह education मिल रही है, जब चाहते हैं तब मिल रही है, जितनी चाहते हैं उतनी मिल रही है, जब job चाहते हैं तब job मिल रहा है, जितना काम चाहते हैं उतना मिल रहा है, जो भी सुख सुविधाएं अथवा products/ services चाहते हैं मिल रही हैं, जितनी चाहते हैं उतनी मिल रही हैं, जब चाहते हैं तब मिल रही हैं, कुल मिलाके आप जैसा जीवन जीना चाह रहे हैं, यदि वैसा जीवन जी पा रहे हैं, इसका मतलब है आप 100% free हैं। Freedom का मतलब उतना space आपको है। माने sky is the limit, माने space is the limit, माने जितना space आप चाह रहे हैं उतना space आपको जीने के लिए मिल जा रहा है हर तरह से, तो वह आपकी ultimate freedom होगी। इस से ज़्यादा कोई freedom चाहता भी नहीं, इस से ज़्यादा कोई freedom होती भी नहीं। रखोगे तो भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कोई आदमी चार रोटी खाता है तो उसको चार रोटी मिल जाए यही उसके लिए ज़रूरी freedom है, अगर आप वहां 20 रोटी रख भी देते हैं तो उसका वहां कोई मतलब नहीं। तो ultimate space हो गया ultimate freedom। आप जितना सुखी होना चाहते हैं और उतना सुखी होने के लिए जो जो चीज़ें, जितनी जितनी मात्रा में चाहिए, उतनी चीज़ें तब तब आपको मिल जाती हैं, जब जब आप चाहते हैं तो यह आपकी ultimate freedom होगी। और इतनी freedom हर व्यक्ति चाहता है, यही उसकी इच्छा होती है।

26) आप यह कैसे कह सकते हैं कि इस नई प्रणाली में तानाशाही की कोई संभावना नहीं है?

जी इसमें तो तानाशाह बनने की गुंजाईश ही नहीं, क्यूंकि जनता द्वारा दिए गए satisfaction ratings से किसी की भी performance rating निकलेगी। तो अगर rating negative में है तो उस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा। Negative performance पर उसकी पदवी चली जाएगी। और तो और जनता चाहे तो negative voting से किसी को कभी भी अपदस्त कर सकती है। इस तरह सारी पावर जनता के हाथ में है। तो तानाशाह होने का तो कोई sense और न ही space दिखाई

पड़ता है। तो कोई तानाशाह होगा कैसे? क्यूंकि जो भी पुलिस और जो भी अधिकारी होंगे वह व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी न की किसी नेता के लिए। और जो पावर है वह सारी लोगों में, लोगों के पास है 24 घंटे, जिस से कोई भी किसी भी स्तर पर तानाशाह बन नहीं सकेगा। तो संभावना ही नहीं है। दूसरी बात सारे क्रिया कलाप online रहेंगे। सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ जनता के सामने है। कोई भी नीति बन रही है, क्यों बन रही है, क्या संवाद हुआ, उस से सम्बंधित शोध, वह सब डाटा व रिकॉर्डिंग सार्वजनिक मंच में रहेगा। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी देख सकेगा। सब कुछ online रहेगा,अलग से RTI फाइल करने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं भी कुछ ढकाव , छुपाव रहेगा ही नहीं जिस से रत्ती भर भी हिटलर शाही कोई कर सके। एक तो ज़रूरत ही नहीं किसी को वैसा होने की दूसरा कोई कोशिश भी करेगा तो संभव ही नहीं है वहां। यहां तक की कोई अपराध होने की संभावना नहीं तो तानाशाही तो अपराधों का अपराध है, यानी घोर अपराध है।

27) नए मॉडल में कार्यपालिका और विधायिका की क्या भूमिका है, क्या यह आज के मॉडल से अलग है?

जी, आज के मॉडल से तो अलग ही है। मतलब इसमें कार्य पालिका और विधायिका ऐसे करके अलग से विभाजन नहीं है। सिस्टम ऐसा है की नेता नीति निर्धारक होंगे और व्यवस्था की देख-रेख यानी शाशन प्रबंधन भी वही करेंगे। उनके अंतर्गत कई विभाग होंगे जो अलग अलग कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होंगे। नेता लोगों को फील्ड में जाने की जरूररत बहुत कम ही पड़ेगी, क्यूंकि सारी जानकारी उनको विभिन्न विभागों से online मिल जायेगी। फील्ड में तो वह दुसरे लोगों को भेज रहे होंगे जिनके inputs पर वह सारी देख रेख कर रहे होंगे, हर चीज़ पे नज़र रख रहे होंगे। Online System में सारा data visualize हो रहा होगा। उसकी देख रेख और नीति निर्धारण उनका काम होगा, बाकी हर आदमी और डिपार्टमेंट का अपना काम होगा। हर यूनिट कुछ न कुछ प्रोडक्शन या सर्विस दे रहा होगा। तो कुल मिलाके प्रशाशन का सारा उत्तरदायित्व नेताओं पर ही होगा, स्पष्ट होगा और जो भी व्यावहारिक समस्याएं आएँगी उनसे वे अवगत रहेंगे। इससे यह होगा की वे ऐसा नीति नियम नहीं बनाएंगे जो अव्यवहारिक हो क्यूंकि प्रशाशन की ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर ही है।

28) नए मॉडल में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या यह आज के मॉडल से अलग है?

एक तरह से आज के मॉडल से मिलती जुलती है और कुछ मामलो में नयी है। नए मॉडल में न्यायपालिका एक supervisory body होगी। नए मॉडल में उसे **संवैधानिक परिषद** कहा गया है। जैसे विधायिका और कार्यपालिका को संयुक्त रूप से **नेतृत्व परिषद** कहा गया है , वैसे विधायिका को **संवैधानिक परिषद** कहा गया है। यह विभाग पूरे नेतृत्व की सुपरवाइजरी कर रही होगी। यह विभाग इस बात पर नज़र रखेगा की सिस्टम ठीक से चल रहा है की नहीं और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो वह नेतृत्व परिषद को उत्तरदायी करेगा, उनसे पूछेगा, जांच आरंभ करेगा इत्यादि। संवैधानिक परिषद एक तरह से अतिरिक्त नेतृत्व है जो तब काम में लाया जायेगा जब नेतृत्व विभाग समस्या के समाधान में असफल हो रहा है। कहीं भी अनियमितता हो रही होगी और वो उन लोगों से एक समय सिमा के अंतर्गत नियंत्रण नहीं हो रही होगी तो वह मामला संवैधानिक परिषद के हवाले हो जायेगा। मुख्यतः यह एक निगरानी रखने वाला विभाग होगा जो हर तरह से ऑडिट करके , चेक कर रहा होगा की पूरे व्यवस्था की परफॉरमेंस कैसे चल रही है, कहीं कुछ कमी तो नहीं आ

रही, इस तरह की assessment agency होगी। यह विभाग हर साल अपना रिपोर्ट देती रहेगी और बताती रहेगी किस परसेंटेज में result अनुकूल या प्रतिकूल हुए, विभिन्न मानकों के आधार से। वो जनता को यह सब बताती रहेगी, एक तो यह काम हुआ। दूसरा यह की आपातकालीन अवस्था में जब मुख्य नेतृत्व असक्षम होगा तो मामला इस विभाग को चला जायेगा। तो यह एक कॉम्प्लिमेंटरी विभाग है मुख्य नेतृत्व का सहायक होने के लिए। यही विभाग हर नीति, नियम, निर्णय का final output से mapping भी करेगा और यही विभाग citizen satisfaction ratings से performance rating भी निकालेगा। तो यह विभाग जनता को feedback भी देता रहेगा और नेताओं को भी। सभी को दो रूपों में feedback देगा - पहला लोगों को कैसा लग रहा है उस सिस्टम में जीवन और दूसरा जो काम कर रहे हैं उनका क्या performance रहा। यह तटस्थ होकर पूरे सिस्टम को देख रहा होगा, समग्र रूप से। चूँकि व्यवस्था का उद्देश्य है सभी लोगों को सुखी करना, तो लोग किन चीज़ों में कितने संतुष्ट हैं, ऐसा रिपोर्ट वह निकालते रहेंगे ताकि संबंधित डिपार्टमेंट उसमें सुधार करे। तो यह विभाग यह सुनिश्चित करेगा की लोकतंत्र में संवाद बना रहे और संवाद का यहां अर्थ है, विभिन्न एक्सपर्ट्स का प्रपोजल जनता तक पहुँच रहा है, ताकि नीति, नियम निर्णय पारित हों और जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंच रहा है। और उस फीडबैक या संवाद को ताकत दी गयी है की उस से किसी का भी पद जा सकता है ।

29) इस नई व्यवस्था में निर्णय कैसे लिए जाएंगे? निर्णय लेने की शक्ति कौन रखता है?

जी, इस व्यवस्था में जो प्राइमरी या पहला निर्णय हैं वह तो सरकार में जो experts हैं वही लेंगे, लेकिन जो अंतिम निर्णय हैं या सेकेंडरी निर्णय हैं वह जनता लेगी।

30) नई व्यवस्था में सरकार के क्या कार्य हैं?

सरकार सारी चीज़ों की देख रेख कर रही होगी, उसमें सब कुछ आ जाता है जैसे - शिक्षा, रोज़गार, मांग और आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा, कुल मिलाकर सब तरह की समाज जनित सुख सुविधाएं। व्यवस्था इसी बात की देख-रेख करने के लिए है की जितने भी नागरिक हैं वो सब 100 % संतुष्ट हैं की नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो उसमें updation करेंगे, सुधार करेंगे और करते रहेंगे जब तक संतुष्टि नहीं आ जाती। चूँकि यह एक केन्द्रीगत ढांचा है और सरकार ही पूरा मैनेजमेंट कर रही है तो उसी के आँखों के सामने सब हो रहा होगा।

Philosophical model

31) आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है?

जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, सुखों की प्राप्ति, यही जीवन का उद्देश्य है।

32) आपके अनुसार मानव क्या है?

मानव एक ऐसा जीव है, एक ऐसा अस्तित्व है जो इच्छा करता है सुखी होने की, विभिन्न प्रकार से सुखी होने की। उसे विभिन्न तरह के ज्ञान करने की, कर्म करने की, भोगों को भोगने की इच्छाएं होती हैं जिस से उसमें विंभिन्नता आती है। तो मनुष्य इस प्रकार की entity है जो ज्ञान, कर्म, भोगों की इच्छा करती है सुखी होने के लिए और निरंतर प्रयास करती रहती है।

33) आपके अनुसार सुख क्या है और दुःख क्या है? सुख कितने प्रकार के होते हैं?

सुख का मतलब है आपको कोई इच्छा हुई और वह इच्छा आपकी पूर्ति हो जाती है। आपको इच्छाएं होती रहती हैं और पूर्ती होती रहती है तो इसी बात को सुख बोलते हैं और यदि आपकी इच्छा हुई और पूर्ति न हुई तो इसी बात को दुःख बोलते हैं। तो यही सुख और दुख है। विभिन्न प्रकार के सुख होते हैं जैसे किसी ज्ञान का सुख होता है, किसी कर्म का सुख होता है, भोगों का सुख होता है, विश्राम करने का सुख होता है। तो इस तरह से कई सारे विषयों में रमण करने का सुख होता है। इसी तरह से उतने सारे दुःख भी होते हैं। तो सुखों को कई तरह से categorize किया जा सकता है जैसे - व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, समष्टिगत सुख। व्यक्तिगत सुखों को भी विभाजित किया जा सकता है जैसे - शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भावनात्मक सुख, चेतनात्मक सुख। व्यक्तिगत सुखों का आधार सत्य है। पारिवारिक सुखों का आधार प्रेम है। सामाजिक सुखों का आधार न्याय है। समष्टिगत सुखों का आधार पुण्य है। ये चारों सुख भी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यदि सामाजिक व्यवस्था सही होती है तो इसका पारिवारिक सुख पर और व्यक्तिगत सुख पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमें सम्पूर्ण व्यवस्था पर ही कार्य करना चाहिए।

34) आपको क्या लगता है कि लोग क्यों हीनता और श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित हैं और दूसरों से क्यों मान्यता चाहते हैं?

वो परिस्थितियों के अनुसार ऐसा हो जाते हैं, क्यूंकि अभी परिस्तिथितियां ऐसी हैं के अगर आप यदि समाज में महान सिद्ध होंगे तो आप की तरफ सभी सुख सुविधाएं बेहनी शुरू हो जाती हैं। Unconsciously यह बात हम लोग सब समझते हैं बचपन से। जब एक माहौल में पढ़ते, लिखते, बढ़ते हैं तो हमें अंदर खाने ऐसा मोटा-मोटा समझ में आता है के जो प्रसिद्द लोग हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो इसलिए आदमी श्रेष्ठ होना चाहता है या दुसरे शब्दों में superior होना चाहता है और जो लोग नहीं हो पाते वे अपने आप को inferior महसूस करते हैं। उन्हें मालूम भी चलता है की उनके पास सारे सुखों की availability नहीं है तो वह अपने आप को inferior महसूस करते हैं। तो यह परिस्तिथि जन्य superiority या inferiority, या कुल मिलाके बोलें तो ख़राब व्यवस्था इसके लिए दोषी है जो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करती है जिसमें कुछ थोड़े से लोग superiority में चले जाते हैं और अपने आप को वैसा अनुभव करते हैं और अधिकतम लोग inferiority में चले जाते हैं और वैसा अनुभव करते हैं। दोनों ही complex हैं , दोनों की अपनी समस्याएं हैं , दोनों ही परेशानियां हैं। Superiority में दुसरे तरह की परेशानियां हैं, कुछ दुसरे लाभ हैं। Inferiority में परेशानियां ही परेशानियां हैं, कोई लाभ की बात नहीं। इसलिए सब superior होना चाहते हैं , inferior होना कोई नहीं चाहता, क्यूंकि कम से कम उसमें कुछ प्रकार के लाभ तो हैं।

Education

35) मौजूदा शिक्षा प्रणाली में आप क्या त्रुटि देखते हैं?

कई प्रकार की त्रुटियाँ है, एक तो शिक्षा बहुत ज़्यादा है, दूसरा बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जाती है, तीसरा ऊंची नौकरियों को लेने के लिए घर वाले भी प्रेशर डालते हैं, चौथा सभी बच्चों को एक ही

स्तर की शिक्षा नहीं है, सभी बच्चों को सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। पांचवा जैसी शिक्षा वे चाहते हैं, वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती। जिस प्रकार के उन्हें नौकरियां चाहिए उस प्रकार के नौरकरियाँ नहीं मिल पाती। तो यह सारी कमियां ही हैं मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में जो मनुष्य पर भार डालती हैं, बोझिल करती हैं,मतलब मुझे ऐसा लगता है की वो उसको फलने फूलने ही नहीं देतीं। वो ऐसा दिखता है की शारीरिक रूप से तो युवा हो रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुर्दा हो गया है, मर-मर के जी रहा है, मतलब खुश नहीं है। शुरू के दो-चार साल जब तक वो खेलता-कूदता है तभी कुछ लगता है जीवन का मज़ा है पर जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है तो लगता है जैसे सज़ा शुरू हो गयी। और जब तक उसकी शिक्षा पूरी होती है 20-25 साल तक तब तक सज़ा से ही गुज़र रहा होता है। अब ऐसा जीवन कैसे युवा होगा , कैसे सुखों से भरा होगा , कैसे 150-200-400 साल जीएगा? कैसे? तो यह सारी शिक्षा बोझिल कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आदमी जो है वास्तव में है और जो वो हो सकता है, वो होने में मदद करे और फिर उस व्यक्ति से उसी प्रकार का सहयोग लिया जाये व्यवस्था में जिससे की विभिन्न प्रकार की भोग सामग्री व सर्विसेज वगैरह पैदा हों ताकि सब लोग सुखी हों।

36) आपके अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है?

शिक्षा वही है जो हमें शिष्ट बनाती हो। जो हमारे अंतःकरण को शिष्ट बनाती हो। शिष्ट से ही मनुष्य सभ्य होता है। सभ्य का अर्थ होता है कि जो समाज बनाया गया है वो उसमें व्यवहार करने योग्य हो जाये। सभ्य का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य कोई बिगड़ा हुआ प्राणी है और उसे शिक्षा देकर सुधारना है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ठीक ही है जैसे कि उसे होना चाहिए। शिक्षा का उददेश्य केवल ये ही होना चाहिए कि वो समाज के नीति नियमों का ज्ञान उसे करा सके ताकि वो सभ्य बन सके यानिकि समाज में व्यवहार करने में सफल हो सके। और उस समाज में उसका कर्म क्या होगा जिससे वो इस समाज के उद्देश्य में अपना योगदान दे सके। इसी के लिए तो समाज की रचना की गई है कि जिसके माध्यम से हम सभी अपने ईच्छित सुखों को प्राप्त कर सकें। शिक्षा के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमें क्यों कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें कैसा आचार और व्यवहार करना चाहिए, ये केवल शिक्षा से ही आसानी से एवं त्वरित गति से जाना जा सकता है। शिक्षा की परिभाषा है - जो हमें सिखाती है, कैसे हम सुखी हों, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करें, कैसी व्यवस्था हमारे पास हो, कैसे हम उस व्यवस्था में एक दुसरे के साथ सहयोगता पूर्वक जीएं, यह सब चीज़ें सिखाने के लिए ही शिक्षा का होना है। किसी प्रोफेशन में, किसी विषय में हमें वह मास्टर बनाती हो, हमें trained करती हो। इसी सबको शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा का मतलब यह बिलकुल नहीं होता की कोई इंसान बुरा होता है और उसे नैतिकता का पाठ पढ़ा-पढ़ा के अच्छा इंसान बनाना है या दूसरी ओर ज़ोर डाल-डाल के अति मुर्ख से अति विद्वान बनाना है, यह दोनों सही दृषिकोण नहीं हैं।

निश्कर्ष ये हुआ कि मानव जीवन के समग्र विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा ही हमें सही अर्थों में सामाजिक बनने में सहायता प्रदान करती है। सामाजिक होने से ही सभी प्रकार के सुखों के द्वार खुलने लगते हैं। समाज के जीवन को समृद्धशाली कैसे बनाया जा सके, सुखसुविधाओं को बढ़ाने के लिए कैसे ज्ञान विज्ञान को खोजा जा सके और कैसे उस ज्ञान और विज्ञान को आने वाली पीढ़ी

तक प्रेषित कर सकें ताकि आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान को सहज ही कम समय में प्राप्त करके उससे आगे की खोजों पर जा सके, और जो खोज लिया गया है उसका प्रयोग जीवन की सुखसुविधाओं को बनाने में प्रयोग किया जा सके जिससे हम अधिक से अधिक सुखी हो सकें। ये ही परिवार, समाज आदि संरचना बनाने का उददेश्य होता है। उसके लिए ही शिक्षा की आवश्यकता होती है।

37) आपके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा व्यवस्था आज के शिक्षा मॉडल से कैसे भिन्न है?

जो नयी शिक्षा व्यवस्था होगी वह बच्चों के हिसाब से होगी, बहुत हलकी होगी, दो घंटे का स्कूल होगा। किसी बच्चे को ज़्यादा रूचि है तो दो घण्टे उसके लिए बढ़ाये जा सकते हैं। उस प्रकार के बच्चों के लिए कोर्स उनके अनुकूल बनाया जायेगा। इस प्रकार से कई प्रकार के अभिनव स्कूली शिक्षा के तरीके मौजूद होंगे जो बच्चों के रूचि के आधार से होंगे। बच्चे चाहे कोई भी विषय सीखें, सब की मान्यता समान होगी। जिस विषय में जहां तक जाना चाहें वहां उनके लिए पूरा प्लेटफार्म होगा। जहां से आगे नहीं जाना चाहें, नहीं जाएँ। जितना सीखना चाहेंगे सीखेंगे, न सीखना चाहें न सीखें, माने इस प्रकार से शिक्षा का वातावरण होगा। इच्छा अनुसार शिक्षा होना चाहिए जिसमें शिक्षा लेने में भी सुख हो और देने वाले को भी सुख हो और यही मूल है नयी व्यवस्था में। कोई दबाव नहीं होगा, खेल-खेल मैं सीखना-सिखाना होगा।

शिक्षा दो प्रकार की होगी- सामान्य और आजीविका परक।**15 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम होगा।** जोकि सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायेगा। कोई भी विद्यार्थी कभी फेल नहीं किया जायेगा। जो जितने नम्बर लेकर आयेगा, उन्हीं नम्बरों के साथ उसको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जायेगा। केवल चार विषय ही इस सामान्य शिक्षा में पढ़ाये जायेंगे। भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन। जोकि सभी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करेंगे। भाषा मन का विकास करेगी, गणित बुद्धि का विकास करेगा, संज्ञान चित्त का विकास करेगी और दर्शन अहंकार का विकास करेगा। अंतःकरण के विकास से ही मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान होता है। कब क्या करना चाहिए उसे इस बात का ज्ञान शिक्षा से ही होता है। आचार व्यवहार कैसा हो ये सब शिक्षा से ही मनुष्य को ज्ञात हो पाता है। इस सामान्य शिक्षा को प्राप्त करके चार प्रकार के व्यक्तित्व निकलकर आयेंगे। शरीरावस्था (Physical quotient) की क्षमता वाले, मानसिक अवस्था (Intellience quotient) की क्षमता वाले, भावनावस्था (emotional quotient) की क्षमता वाले और चेतनावस्था (consciousness quotient) की क्षमता वाले।

सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 6 वां वर्ष में बच्चे का विद्यालय में पंजिकरण करके प्रथम कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। 20 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा सामान्य शिक्षा पूर्ण करेगा। अंत में विद्यालय के द्वारा सभी बच्चों की वरीयता निश्चित की जायेगी। तत्पश्चात् उनकी वरीयता और इच्छानुसार किसी एक विषय का आजीविका परक ज्ञान अगले 5 वर्षों तक दिया जायेगा। उसे महाविद्यालय कहा जायेगा। जिसके आधार पर सभी को एक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके पश्चात् शोधपरक शिक्षा के अंतर्गत केवल योग्य विद्यार्थी ही अपनी इच्छानुसार शोधानुसंधान की शिक्षा जारी रख सकेंगे। इसे विश्वविद्यालय कहा जायेगा। जोकि इनका रोजगार भी होगा।

पांच वर्शीय प्रषिक्षण विधान के अंतर्गत चार प्रकार के प्रशिक्षण होंगे, चार प्रकार के व्यक्तित्वों के लिए

1.कृषिक शिक्षा 2. व्यावसायिक शिक्षा 3. प्रशासनिक शिक्षा 4. नेत्रत्व शिक्षा

षोधानुसंधान विधान
इसके अंदर शोधकार्य होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न विषयों में शोधकार्य होते रहेंगे। शोधकार्य करने वाले को वैज्ञानिक की उपाधि से ही जाना जायेगा। शोधानुसंधान शिक्षा को तीन भाग में रख सकते हैं। ये भी तीन श्रेणियों में ही होंगे। जिस प्रकार आपके शरीर, मन, प्राण होते हैं। उसी प्रकार समष्टि में भी पदार्थ, प्रकृति और प्राण होते हैं। पदार्थ के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आधिभौतिक विज्ञान, प्रकृति के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आधिदैविक विज्ञान और प्राण के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आध्यात्मिक विज्ञान।आधिभौतिक शिक्षा, आधिदैविक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा, ये तीन प्रकार की शोधानुसंधान शिक्षा होगी है। आधिभौतिक शिक्षा के अंतर्गत चारों प्रकार की आजीविका कृषि, व्यावसायिक, प्रशासन, नेत्रत्व का अध्यन एवं शोध कार्य आता है। आधिदैविक शिक्षा के अंतर्गत पूरी प्रकृति का अध्यन एवं शोध कार्य आता है। और आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत प्राण का अघ्ययन एवं शोध कार्य आता है। तो संक्षेप में यह संपूर्ण समाधान का शिक्षा का ढांचा है।

Transition

38) हम यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचे?

जी यह सब बहुत सुगमता से होगा, बिना किसी को परेशानी पहुंचाए। सबसे पहले हम इस व्यवस्था के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग इसको अच्छे से समझ के निर्णय कर लें की यह व्यवस्था लानी है की नहीं लानी है। इसके लिए **खुला मंच** नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भी विभिन्न माध्यमों से लोगों तक यह समाधान पहुंचाया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को लेकर सभी दृष्टिकोण से वार्ता होगी। अगर सर्वे करने के बाद यह पता चलता है की जनता इसके साथ है और उनको लगता है की लानी चाहिए तो संवैधानिक रूप से फिर बात आगे बढ़ेगी ताकि यह व्यवस्था मौजूदा सरकार या नयी सरकार द्वारा स्थापित हो। यानी मौजूदा व्यवस्था द्वारा नयी व्यवस्था स्थापित हो। अगर बहुमत इसको चाहेगा तो यह इलेक्शन का मुख्य मुद्दा बनेगा और समाज इसके लिए पहले से तत्पर होगा क्यूंकि इस विषय पर समाज में काफी चर्चा हो चुकी होगी और मन बन चूका होगा। कुछ ही समय में इस विषय के ऊपर में नयी किताब लांच करने वाला हूँ जो यह बताएगा की step by step, संवैधानिक रूप से मौजूदा व्यवस्था से नयी व्यवस्था में कैसे shift होगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी क्रान्ति के, बिना किसी टकराव के, उस किताब को पढ़ कर आप यह जान पाएंगे। जब नयी व्यवस्था लॉन्च होगी तो पहले कुछ नियमों में बदलाव होगा और एक transition चलेगा आज की व्यवस्था से विकेन्द्रीगत- केन्द्रीगत व्यवस्था में। उसके लिए सॉफ्टवेयर आदि बनेंगे , इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का ब्लू प्रिंट बनेगा, इत्यादि। यह 2-3 साल का transition phase होगा। केन्द्रीकरण होने के पश्चात शुरुवात में ही सबकी salary बराबर कर दी जाएगी, सबके श्रम का मूल्यांकन बराबर हो जायेगा । इस तरह से phases में यह व्यवस्था लायी जाएगी, जिस में हर नया

दिन ज़्यादा सुखदायी होगा सभी के लिए। जितनी जितनी तैयारी होती जाएगी, सम्बंधित नियम लागू होते जायेंगे और 2-3 साल में transition पूर्ण होगा।

39) "खुला मंच"आयोजन की रूप रेखा क्या है और कैसे काम करेगा?

खुला मंच जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सभी वो लोग जिन्हें लगता है की उनके पास उन्हीं के द्वारा खोजा हुआ कुछ ऐसा है जो समाज को आज से ज़्यादा सुखी कर सकता है या उनकी कोई धारणा में, उनके कोई धर्म ग्रन्थ या कोई पुरानी पुस्तक जिसमें उन्हें लगता है कोई व्यवस्था, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ऐसा है जो उन्हें लगता है लाभकारी है, तो उन सबको खुला आमंत्रण है। हम आमंत्रण भेजेंगे ही जैसे ही हमें पता चलेगा की समाज में वह कुछ दावा कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए, उनसे भी यह अपेक्षा रहेगी की खुले मंच में आकर वह अपना समाधान बताएं। इस सामाजिक मंच में प्रश्न पूछे जायेंगे के उनके पास जो कुछ है वह कैसे समाज को सुखी करेगा। तो अगर वो उसको वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रस्थापित कर पाते हैं तो उसको सामाजिक रूप से अपना लिया जाएगा और अगर नहीं है तो फिर प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ दिया जायेगा। और अगर यह पाया जाता है की वह बेकार है तो बेकार का टैग लगा दिया जायेगा। अगर वे उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया जायेगा ताकि जो भी उस दावे को जब भी सिद्ध करना चाहे, आकर सिद्ध कर सकता है। जो बात जब भी सिद्ध हो जाएगी उसको स्वीकृति मिल जायेगी। चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए आपको अपने दावे के अनुसार तर्क से और प्रमाणों से बात रखनी होगी। क्यूंकि सब लोग सभी विषयों के एक्सपर्ट्स नहीं होते तो, तो सब लोग प्रश्न भी नहीं कर पाते गहरे से, जिस से समाज में भ्रम की स्तिथि बनी रहती है लगातार। **क्यूंकि एक्सपर्ट्स ही समाधान दे सकते हैं और एक्सपर्ट्स ही सही विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए खुला मंचा सभी एक्सपर्ट्स को एक जगह एकत्रित कर रहा है।** जो विषय की समझ रखते हैं उसको पेश करेंगे और सवाल जवाब होने पर लोगों को समाधान वाला पक्ष सरलता से समझ आएगा। सवाल जवाब होने पर एक वस्तु स्तिथि का ज्ञान होगा और लोगों को पता चलेगा की वह प्रस्ताव उनके काम का है की नहीं। यदि वह प्रस्ताव उनके सुख को बढ़ाएगी तो वो उसका समर्थन करेंगे अन्यथा नकार देंगे। तो इस तरह से समाज में जो कई सारे प्रचलित समाधान चल रहे हैं वह एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और समाज भ्रम की स्तिथि से निकल पायेगा और एक स्पष्ट दिशा निर्धारण होगा।

40) यदि एक राष्ट्र में यह व्यवस्था को अपनाया जाता है, तो यह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कैसे व्यापार करेगा?

जब तक यह व्यवस्था सभी राष्ट्रों में नहीं आ जाती या जिन राष्ट्रों में नहीं आ जाती तो इन राष्ट्रों के साथ उसी प्रकार व्यवहार होगा जैसा अभी चल रहा है, माने इंटरनेशनल मुद्रा यानी hard currencies इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था की मुद्रा रख सकते हैं बाह्य चलन के लिए अगर उसकी वैल्यू होती है इंटरनेशनल मार्किट में। तो वहां ऐसे चलता रहेगा व्यापार जैसे आज चल रहा है, आवश्यकता अनुसार, नए सिस्टम और दुसरे देशों के व्यापारियों के बीच।

41) यदि विदेशी पर्यटक ऐसे देश में आते हैं, जिन्होंने इस नई व्यवस्था को अपनाया है, तो वे बिना पैसे के चीजें कैसे खरीदेंगे?

जी जब वे संपूर्ण समाधान व्यवस्था में प्रवेश करेंगे तो उन्हें डॉलर या कोई अंतर राष्ट्रीय हार्ड करेंसी जमा करनी पड़ेगी । उनको एक debit card मिल जाएगा, या वे अपने मोबाइल में सरकार द्वारा जारी Application डाउनलोड कर सकते हैं, या सरकार द्वारा जारी कोई gadget उन्हें प्राप्त होगा जिसमें सभी प्रोडक्ट्स/ सर्विस के रेट दिए होंगे अंतर राष्ट्रीय करेंसी इत्यादि में, जिससे वे कोई ट्रांसक्शन कर सकते हैं। उस कार्ड से जो कुछ भी सुख सुविधा लेंगे, खाना-पीना, रहना, खरीदना कुछ भी, तो वो उनके कार्ड वाले खाते से कटता रहेगा, जब वे वापिस जाएंगे तो बचा हुआ पैसा वापिस हो जाएगा। और बीच में खत्म हो गया तो अपने देश के बैंक अकाउंट से उस कार्ड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में कोई सीमा भी नहीं रहेगी की आप तीन महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते या Visa के लिए बड़ी जद्दोजहत करनी पड़े और भारी फीस देनी पड़े इत्यादि। यहां सीधे आईये, अपना कार्ड बनवा लीजिये,अपने देश के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लीजिये और जब तक चाहें आनंद उठाइये।

Future Outcomes

42) इस व्यवस्था से परिवारों के भीतर हिंसा कैसे रुकेगी?

इसमें परिवार में भी सभी आर्थिक रूप से व्यवस्था पर ही निर्भर होंगे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पति, पत्नी, जिसको जो चाहिए वह व्यवस्था से मांग करेगा तो एक दुसरे पे कोई भार नहीं होगा। रिश्ते जो भी बनेंगे वे प्रेम के आधार से बनेंगे। एक तो साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं होगी और दूसरा यह है की अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करेगा तो उस पर केस हो जायेगा। उसके ऊपर जो भी दंड बनेगा वह दिया जाएगा, सिस्टम से बर्खास्त भी किया जा सकता है। एक तो कोई ऐसी हिंसा करेगा नहीं, और अगर किया तो दंडनीय होगा।

43) यह व्यवस्था जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेगी?

जी इसमें प्रदुषण पैदा ही नहीं होगा तो रोकने की कोई बात ही नहीं। इसमें सारे processes इस तरह से managed हो रहे होंगे की कहीं भी प्रकृति को, मनुष्य जीवन को या दुसरे जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। इसमें नगरीय व्यवस्था है। 2-5 लाख के नगर बसे होंगे। कम घनत्व होने के कारण प्रदुषण नहीं पैदा होगा। एक पूरा waste recycling system होगा। जल की भी दिक्कत नहीं होगी। नहरों का जाल बिछा होगा, जंगल भी काफी रहेंगे। पेड पौधे होने के कारण हवा भी शुद्ध रहेगी। अनियंत्रित आर्थिक क्रियाएं नहीं हो रही होंगी। जीव जंतु भी पर्याप्त पनप रहे होंगे जिससे जैविक विविधता बनी रहेगी और स्थिर eco-system बना रहेगा। यह सब वैज्ञानिकों की देख रेख में हो रहा होगा।

44) नई व्यवस्था से धार्मिक उन्माद एवं टकराव कैसे रुकेंगे?

जी इसके लिए नयी व्यवस्था में एक नियम होगा छोटा सा। वह नियम है आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते के जब आप उनका पालन कर रहे होंगे तो किसी को कोई वास्तविक परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक मान्यता दुसरे की मान्यता से मेल नहीं खाती तो उस की बात नहीं कर रहा। जो भी जीवन की वास्तविकता है, वास्तविक दिक्कत अगर कोई किसी और के जीवन में अगर खड़ा करेगा तो वह अपराध कहलायेगा। जैसे मान्यता के कारण अगर कोई व्यक्ति

कहीं शोर मचाएगा, कहीं कोई सड़क जाम करके जुलुस निकालेगा तो यह सब अपराध कहलाया जाएगा जो दंडनीय होगा। विभिन्न धर्मो के आयोजनों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, रिहाइशी इलाके से दूर, वहाँ पे वे जमा होके वे अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। वापस जब समाज में आएं तो शांतिपूर्वक रहना पड़ेगा। दूसरी बात,आप अपनी मान्यता को दुसरे के ऊपर आरोपित नहीं करेंगे। कोई freely आपके साथ जाना चाहता है जाए, न जाना चाहता है न जाए।अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वह अपराध कहलायेगा और दंडनीय होगा। तीसरा इसका आप psychological पहलू देखो, के लोग इस प्रकार के धार्मिक rituals क्यों चाहते हैं ? वे इसलिए चाहते हैं के उनके मौजूदा जीवन में कई तरह के दुःख हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख का अभाव है, तो वे इन rituals के आधार से ही थोड़े बहुत सुखी हो लेते हैं, कहीं लोग इक्कठा हो लेते हैं, चार लोग हंस बोल लेते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा बहुत महत्व बना हुआ है। दुखी हों तो मंदिर, मस्जिद, चर्च या दुसरे देवालयों में जाके ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह के सामने गिडगीडा लेते हैं, उनका दुःख हल्का हो जाता है, मानसिक सम्बल मिलता है की चलो शायद कोई तो है जो हमें देख रहा है, स्वर्ग नर्क की बातें, यहां नहीं तो वहाँ सुखी हो जाएंगे इत्यादि। यह चीज़ें इस तरह से लोगों को मदद करती हैं। जब यह व्यवस्था आ जाएगी और सब लोग सभी प्रकार से सुखी हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता परमात्मा से कोई कुछ मांगने जाएगा। यह जो धारणाएं हैं, यह जो rituals हैं, इनका कोई मतलब नहीं बचेगा। यह आप देख ही सकते हैं की बहुत प्रगतिशील अमीर परिवारों में कोई इन्हें पालता नहीं। तो यह धीरे-धीरे जीवन में असंगत हो जाएंगे। तो यह जब तक बने हुए हैं, इस प्रकार से रह सकते हैं। किसी को हानि न करें और कोई चीज़ बनी रहे तो क्या दिक्कत है? और व्यवस्था उनको पूरा मौका देगी अगर उनके पास कोई भी ऐसा ज्ञान है जो समाज के लिए हितकारी है तो उसको समाजीक मंच में साबित करें, फिर वह मान्यता नहीं रहेगी बल्कि जानने में आ जाएगी। लेकिन जब तक बात साबित नहीं हो जाती उस से पहले अनेको मान्यताएं व्यक्तिगत मामला ही रहेगा।

45) यह नई व्यवस्था जातिवाद को कैसे संबोधित करेगी?

जी पहले तो देखें जातिवाद किस कारण से बना हुआ है समाज में। जातिवाद बने रहने के कारण दो हैं। एक तो असमानता है, और आर्थिक असमानता इसमें मुख्य है जिसमें उनको वैसा जीवन स्तर, वैसी शिक्षा नहीं मिलती, तो वह उस तरह से उठना, बैठना, रहना, साफ़-सफाई, ऐश्वर्य मेल नहीं खाते। जो लोग अलग स्तर से जीवन जी रहे हैं, तो वे एक दुसरे से कैसे व्यवहार करें, कैसे कोई सम्बन्ध रखें? उनकी मैचिंग नहीं होती, जब वो एक जैसा जीवन नहीं जीते। दूसरा कोई भी व्यवहार बराबरी में ही ठीक से चल पाता है। बहुत ज़्यादा उंच नीच में कोई भी सम्बन्ध ठीक से चलता भी नहीं। इस प्रकार से भी दुराव रहता है। और यही सब बातें परंपरा में प्रवेश करके सामाजिक ढाँचे का रूप ले लेती हैं। लेकिन यह सब नहीं रहेगा जब आर्थिक समानता हो जाएगी। जब सभी को बराबर शिक्षा और सूख सुविधा मिलेगी तो इस चीज़ का कोई मूल्य नहीं बचेगा। सिस्टम में कुछ पूछा नहीं जाएगा,आप का धर्म क्या है,आपकी जाती क्या है। तो धीरे-धीरे अपने आप यह चीज़ विलुप्त हो जायेगी। जिस चीज़ की कोई प्रासंगिकता नहीं बचती वह अपने आप ही विलुप्त हो जाती है, वो नहीं रहती। इस तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो जायेगा। और जो कोई लोग रखेंगे भी तो रखें, उस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूंकि जैसा जीवन जीना है वो तो जी सकेगा। वह कोई अपने आप को भारद्वाज , वाल्मीकि, या SC/ST बोले बोलता रहे , किसी को अच्छा लगता है बोलो अपने लिए।

प्रेमजीत सिरोही के बारे में

प्रेमजीत सिरोही एक वक्ता, लेखक एवं दार्शनिक हैं। वे यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था के संस्थापक भी हैं। यह संस्था वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने के लिए एक थिंक टैंक है। प्रेमजीत सिरोही जी की पुस्तक सम्पूर्ण समाधन-(एक नयी सामाजिक राजनैतिक अर्थव्यवस्था) मानव जीवन की सभी समस्याओं के लिए एक नयी व्यवस्था की पेशकश करती है, जिसमे सभी मनुष्य समान रूप से सुखी हो सकेंगे। उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं और देश विदेश में विभिन्न मंचों पर भाग लेकर इस समाधान को जन जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। उनके व्याख्यानों में अर्थ शास्त्र, राजनीती शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र से लेकर मनोविज्ञान तक जैसे कई विषयों का समावेश होता है। उनके निष्कर्ष बहुत ही अनोखे, मौलिक और अकादमिक परंपरा में अनसुने हैं ।

संपूर्ण समाधान विस्तृत संस्करण हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं

https://lnkd.in/gdz3J-m @

अधिक जानने के लिए आप हमसे इन प्लेटफॉर्म्स में जुड़ सकते हैं

आपका धन्यवाद

ULM Team